संस्थापक : स्व. श्री वीर विक्रम आदित्य

हिन्द जनपथ

स्थापना वर्ष : 2002

पंचकूला
गुरुवार
8 जनवरी, 2026
वर्ष:24 अंक: 196
कुल पृष्ठ:08
मूल्य : 1 रुपया

खबरें छापते हैं छुपाते नहीं | दैनिक प्रभात संस्करण हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश से एक साथ प्रकाशित। | www.hindjanpath.com

जीरामजी योजना का उद्देश्य हर हाथ को काम और हर चेहरे पर मुस्कान लाना है: विपुल गोयल

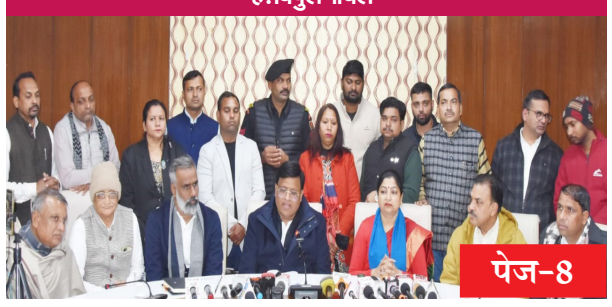

पेज-8

'युद्ध नशे के विरुद्ध' दूसरा चरण शुरू

'युद्ध नशे के विरुद्ध' के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने कहा, 'एकजुट होकर पंजाब नशे को जड़ से खत्म कर देगा'

हिन्द जनपथ
चंडीगढ़ (ब्यूरो)। पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई को तेज करते हुए, आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में 'युद्ध नशे के विरुद्ध' के दूसरे चरण की शुरुआत की, जिससे राज्य की चल रही कार्रवाई को एक व्यापक जन आंदोलन में बदल दिया गया। यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए, AAP प्रमुख ने पहले चरण के ठोस परिणामों का हवाला दिया, जिसमें तस्करों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई, उच्च दोषसिद्धि दर और बढ़ती सार्वजनिक भागीदारी शामिल है, और कहा कि चरण II इन उपलब्धियों को मजबूत करेगा ताकि पूरे पंजाब में नशीले पदार्थों के नेटवर्क को निर्णायक रूप से खत्म किया जा सके। सभा को संबोधित करते हुए, AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, "'युद्ध नशे के विरुद्ध' (नशे के खिलाफ युद्ध) के पहले चरण की शानदार सफलता के बाद, आज दूसरा चरण शुरू हो रहा है। पहला चरण लगभग दस महीने पहले 1 मार्च 2025 को शुरू किया गया था, और जिस ईमानदारी, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ इसे लागू किया गया, वैसा न सिर्फ पंजाब में बल्कि देश के किसी भी राज्य में नशे के खिलाफ लड़ाई में पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसा नहीं है कि नशा सिर्फ पंजाब में बिकता है। हरियाणा, गुजरात, दिल्ली और कई अन्य राज्यों सहित ऐसे कई राज्य हैं, जहां नशा खुलेआम और बड़ी मात्रा में बिकता है, लेकिन वहां की सरकारों को इसकी कोई परवाह नहीं है।"

AAP सरकार बनने से पहले की स्थिति को याद करते हुए, AAP प्रमुख ने आगे कहा, "पंजाब में, हमसे पहले, जब

शिरोमणि अकाली दल (SAD) की सरकार सत्ता में थी, तो उनके शासनकाल में हर गली और हर घर में नशा पहुंचाया जाता था। यह उसी समय की बात है जब पंजाब नशे में इतना बुरी तरह फंस गया था कि 'उड़ता पंजाब' फिल्म बनी। पंजाब ने देखा कि नशा घरों में घुस रहा था, और उनके कई बड़े नेता सीधे तौर पर नशा बेचने में शामिल थे। उसके बाद, कैप्टन अमरिंदर ने गुटका साहिब पर कसम खाई और कहा कि वह तीस दिनों या साठ दिनों में नशे को खत्म कर देंगे। उनकी सरकार पांच साल चली और कुछ नहीं हुआ। वे झूठी कसमें थीं। उसके बाद हमारी सरकार आई।"

विस्तार से बताते हुए, अरविंद केजरीवाल ने कहा, "हमें थोड़ा समय लगा क्योंकि उचित तैयारी की जरूरत थी, लेकिन पिछले साल 1 मार्च के बाद, जिस तीव्रता और साहस के साथ हमने नशे के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, वह अभूतपूर्व था। कई लोगों ने हमें चेतावनी दी कि नशा तस्कर बहुत खतरनाक होते हैं, कि वे बड़े गैंगस्टर, अपराधी और गुंडे हैं, और वे हमारे परिवारों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमने कहा नहीं, हम लोगों से यह वादा करके आए हैं कि हम पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य सुरक्षित करेंगे।" कार्रवाई के पैमाने के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "पिछले दस महीनों में, ड्रग तस्करों के खिलाफ 28,000 मामले दर्ज किए गए हैं। इतने बड़े पैमाने पर, आज़ादी के बाद के पचहत्तर सालों में, देश के किसी भी राज्य ने इतने ज़्यादा मामले दर्ज नहीं किए हैं। ये फर्जी मामले नहीं हैं। जब ये मामले अदालतों में पहुंचे और FIR की जांच की गई, तो 88 प्रतिशत मामलों में आरोपियों को जेल भेजा गया। अगर ये फर्जी मामले होते, तो वे खत्म हो जाते, लेकिन पुलिस द्वारा पकड़े गए लोग जेल जा रहे हैं और अदालतों द्वारा उन्हें सज़ा दी जा रही है।

हर 100 मामलों में से 88 मामलों में जेल का आदेश दिया गया, और अब तक अदालतों में पहुंचे 28,000 मामलों में से 88 प्रतिशत में जेल की सज़ा हुई है।"

आर्थिक वृद्धि 7.4 प्रतिशत रहने, जीडीपी के पहली बार 200 लाख करोड़ को पार करने का अनुमान

नयी दिल्ली- सेवा क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन और घरेलू उपभोग तथा निवेश की मांग के समर्थन से चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर 7.4 प्रतिशत रहने और इसके पहली बार 200 लाख करोड़ के पार पहुंचने की संभावना है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने बुधवार को इस साल 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया। इसमें कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी 201.90 लाख करोड़ रुपये पर रहने का अनुमान है। पहली बार ऐसा होगा कि जीडीपी 200 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को छुएगा।

इस तरह चालू वित्त वर्ष में भी भारत विश्व की सबसे तेजी से वृद्धि कर रही अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

आम बजट से पहले जारी अनुमानों के अनुसार, इस वर्ष पूंजी निर्माण में 7.8 प्रतिशत और निजी खपत में सात प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है।

अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ जीडीपी 187.97 लाख करोड़ रुपये था।

उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 7.8 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। रिजर्व बैंक ने पूरे वित्त वर्ष में विकास दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।

भू-राजनैतिक चुनौतियों, अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने और रुपये के ऐतिहासिक निचले स्तर तक उतरने के बावजूद यह वृद्धि दर वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। सरकार के उपभोग बढ़ाने के उपायों का असर भी अर्थव्यवस्था पर देखा जा रहा है। सरकार ने इसके लिए आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये सालाना कर दी है। साथ ही ज्यादातर सामानों पर वस्तु एवं सेवा कर की दरों में 22 सितंबर से कटौती की गयी है।

बजट पूर्व परामर्श बैठक सहभागी लोकतंत्र व साझा उत्तरदायित्व का प्रतीक- मुख्यमंत्री

हिन्द जनपथ
चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को गुरुग्राम में दो सत्रों में विभिन्न हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक में सार्थक चर्चा कर पेरेशवरों के सुझाव सुने। दूसरे सत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्तागण, आर्किटेक्ट्स और पर्यावरणविदों, डॉक्टर सहित विभिन्न पेशेवर शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठकों में दिए गए सुझाव सहभागी लोकतंत्र, सहयोगात्मक शासन और साझा उत्तरदायित्व का प्रतीक है। इस जन भावना पर ही हरियाणा सरकार नीतियों और निर्णयों की नींव रखती है।

हितधारकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवर खुले मन, स्पष्ट सोच और रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ एक मंच पर एकत्र हुए हैं। समाज के प्रबुद्ध वर्ग से जुड़े होने के कारण नीति-निर्माण, विधिक परामर्श, वित्तीय अनुशासन, नियोजन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के

क्षेत्र में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सुशासन की मजबूत इमारत इन्हीं मजबूत स्तंभों पर खड़ी होती है।

बीते वर्ष हितधारकों से मिले सुझाव के महत्व पर बात करते हुए श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जन हित में सुझाव बेहद व्यावहारिक रहे। उनमें दूरदर्शिता और भविष्य की जरूरतों की स्पष्ट झलक दिखाई दी। बीते वर्ष कुल 43 में से 15 सुझावों को बजट 2025-26 में शामिल भी किया गया। इन सुझावों के अंतर्गत वन टाइम सेटलमेंट योजना, ई.टी.ओ. द्वारा धारा-61 के तहत सुओ मोटो जांच, जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा-66 के अंतर्गत स्पेशल ऑडिट हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट पैनल का गठन, ई.टी.ओ. एवं डी.ई.टी.सी. कार्यालयों में पारदर्शिता हेतु सी.सी.टी.वी की व्यवस्था शामिल है। इनके अलावा, कृषि उपकरणों पर जी.एस.टी. में छूट, जी.एस.टी. रिफंड प्रक्रिया का स्वचालन, ई-वेस्ट प्रबंधन की नई नीति, अरावली जंगल सफारी जैसी पर्यावरणीय पहल, प्राणवायु देवता पेंशन योजना और पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र जैसे दूरगामी महत्व के निर्णय भी शामिल हैं। ये सभी निर्णय सरल कर प्रणाली, पारदर्शी प्रशासन, पर्यावरण संरक्षण और जनहित की दिशा में ठोस संकल्प का प्रमाण बने।

वेनेजुएला अमेरिका को 30-50 मिलियन बैरल तेल देगा: ट्रंप

वाशिंगटन- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वेनेजुएला अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल तेल देगा और यह तेल बाजार दरों पर बेचा जाएगा एवं इससे होने वाली कमाई अमेरिकी सरकार के नियंत्रण में रहेगी।

श्री ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि वेनेजुएला में अंतरिम सरकार अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल उच्च गुणवत्ता वाला तेल सौंपेंगे।' उन्होंने कहा कि इससे होने वाली कमाई से वेनेजुएला और अमेरिकी दोनों नागरिकों को फायदा होगा।

श्री ट्रंप ने लिखा, 'यह तेल बाजार मूल्य पर बेचा जाएगा और पैसा मेरे द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में नियंत्रित किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका उपयोग वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों के फायदे के लिए किया जाए।'

उन्होंने ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट को बिना किसी देरी के इस योजना को लागू करने का निर्देश दिया। तेल को जहाजों में भरकर सीधे अमेरिकी बंदरगाहों पर उतारने के लिए भेजा जाएगा। यह घोषणा अमेरिकी सेना द्वारा तीन जनवरी को 'बड़े पैमाने पर हमले' के कुछ दिनों बाद हुई है। हमले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर गत शनिवार शाम को न्यूयॉर्क लाया गया था और उन्हें ब्रुकलिन में मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर एक नए आरोप पत्र में, जिसे अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने साझा किया है, आरोप लगाया गया है कि मादुरो 'राष्ट्र-प्रायोजित गिरोह' चलाते थे और देश में नशीले पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा देते थे।

मोदी और नेतन्याहू ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने तथा गाजा शांति योजना पर बात की

नयी दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भारत- इजरायल रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों और गाजा शांति योजना पर चर्चा की। बातचीत के बाद श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा , ' मुझे अपने मित्र, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके और उन्हें तथा इज़राइल के लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देकर प्रसन्नता हुई। हमने आने वाले वर्ष में भारत–इज़राइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

हमने क्षेत्रीय स्थिति पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया और आतंकवाद के खिलाफ और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने के अपने साझा संकल्प की एक बार फिर पुष्टि की।' प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि श्री नेतन्याहू ने श्री मोदी के साथ बातचीत के लिए टेलीफोन किया था। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ नववर्ष की शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया और दोनों देशों के लोगों के लिए शांति और समृद्धि की कामना की।

उन्होंने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, गहरे आपसी विश्वास और दूरदर्शी दृष्टिकोण के मार्गदर्शन में आने वाले वर्ष में भारत–इज़राइल रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने के लिए साझा प्राथमिकताओं की पहचान की।

मोटी-मोटी बातें

लुधियाना में टारगेट किलिंग की साजिश नाकाम; खालिस्तान कमांडो फोर्स से जुड़े दो आरोपी एक पिस्तौल सहित काबू

हिन्द जनपथ
चंडीगढ़ (ब्यूरो)। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत, खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) एसएएस नगर ने काउंटर इंटेलिजेंस लुधियाना के समन्वय से, विदेशी हैंडलरों के निर्देशों पर टारगेट किलिंग की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे लुधियाना-आधारित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक 9 एमएम पिस्तौल तथा पांच जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान करनबीर सिंह निवासी हैबोवाल कलां, लुधियाना तथा अवतार सिंह निवासी न्यू शिमलापुरी, मिलरगंज, लुधियाना के रूप में हुई है। आरोपी अवतार सिंह का आपराधिक पृष्ठभूमि है और उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट तथा आईपीसी एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी खालिस्तान कमांडो फोर्स (केसीएफ) से जुड़े यूके और जर्मनी आधारित हैंडलरों के संपर्क में थे और कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने अपने हैंडलरों के निर्देशों पर साजिश के तहत लुधियाना में सरकारी तथा प्रमुख कार्यालयों की रेकी की थी।

डीजीपी ने बताया कि जांच से यह भी सामने आया है कि दोनों आरोपियों को कुछ अन्य चिन्हित व्यक्तियों से संबंधित जानकारी एकत्र करने और जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने का कार्य सौंपा गया था।

इस ऑपरेशन की जानकारी देते हुए एआईजी एसएसओसी एसएएस नगर डी सुधरविजी ने बताया कि क्षेत्र में टारगेट किलिंग की साजिश रचे जाने संबंधी विश्वसनीय सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसएसओसी एसएएस नगर की एक संयुक्त टीम ने काउंटर इंटेलिजेंस लुधियाना के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया और दोनों आरोपियों को लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान अवतार सिंह के खुलासे पर उसके कब्जे से एक 9 एमएम पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

एआईजी ने बताया कि जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी कट्टरपंथी थे और इन्हें विदेशी हैंडलरों द्वारा भर्ती कर सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी सामग्री साझा करने का कार्य सौंपा गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में आगे-पीछे के संबंध स्थापित करने के लिए आगे की जांच जारी है।

नगर निगम पंचकूला के आगामी चुनावों को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आरक्षित सीटों का निकाला ड्रा

हिन्द जनपथ
पंचकूला (ब्यूरो)। नगर निगम पंचकूला के आगामी चुनावों के लिए आरक्षित सीटों का ड्रा आज उपायुक्त एवं समिति के अध्यक्ष श्री सतपाल शर्मा की उपस्थिति में उपायुक्त कैंप कार्यालय में निकाला गया।

इस अवसर पर समिति के सदस्य नगर निगम के संयुक्त आयुक्त गौरव चौहान , डीएमसी विनोद नेहरा, सहायक नगर योजनाकार दीपक, नगर निगम के जेई सुशील कुमार सहित गैर-सरकारी सदस्य रितु गोयल, सोनू बिडला एवं जय कुमार कौशिक उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त बैठक में नगर निगम पंचकूला के पूर्व मेयर श्री कुलभूषण गोयल तथा पूर्व पार्षद गौतम प्रसाद एवं राजेश भी मौजूद रहे।

आरक्षित सीटों का ड्रा पर्ची प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी तरीके से निकाला गया। महिला अनुसूचित जाति सीट के लिए तीन पर्चियाँ डाली गईं, जिनमें से वार्ड नंबर 16 को महिला अनुसूचित जाति आरक्षित घोषित किया गया। इसी प्रकार वार्ड नंबर 7 एवं वार्ड नंबर 17 को अनुसूचित जाति (एससी) वार्ड, वार्ड नंबर 19 को बीसीए महिला आरक्षित वार्ड तथा वार्ड नंबर 18 को बीसीबी महिला आरक्षित वार्ड घोषित किया गया। इसी प्रकार सामान्य (महिला) वर्ग के लिए चार वार्ड आरक्षित घोषित किए गए, जिनमें वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 11 एवं वार्ड नंबर 15 शामिल हैं।

बांग्लादेश को भारत में ही खेलना होगा, मैच शिफ्ट करने की मांग ICC ने ठुकराई

ढाका: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के दौरान भारत में होने वाले बांग्लादेश के मैचों को श्रीलंका स्थानांतरित करने का आग्रह किया गया था। ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, आईसीसी ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश को भारत आकर ही अपने निर्धारित मुकाबले खेलने होंगे, अन्यथा अंक गंवाने का जोखिम रहेगा।

रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को आईसीसी और बीसीबी के बीच वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें 'सुरक्षा चिंताओं' के आधार पर मैच स्थान बदलने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि, इस बैठक के नतीजों पर अभी तक आईसीसी या बीसीबी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है।

भारत में बांग्लादेश के तय मुकाबले

बांग्लादेश अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन्स में करेगा। इसके बाद 9 फरवरी को इटली से और फिर 2022 के चैंपियन इंग्लैंड से भी कोलकाता में ही मुकाबला प्रस्तावित है।

इसके बाद टीम मुंबई जाकर नेपाल के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेलेगी। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला 7 फरवरी को पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच कोलंबो में होगा। बीसीबी ने इससे पहले एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि 'सुरक्षा और संरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं' के चलते मौजूदा परिस्थितियों में बांग्लादेश की टीम भारत की यात्रा नहीं करेगी। बोर्ड के अनुसार, यह फैसला निदेशक मंडल की आपात बैठक और बांग्लादेश सरकार की सलाह के बाद लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के लिए टीम से बाहर करने का फैसला भी चर्चा में रहा। यह कदम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के निर्देश के बाद उठाया गया था। बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया ने कहा था कि हालिया घटनाक्रम को देखते हुए फ्रेंचाइजी को यह निर्णय लेने को कहा गया।

STF हरियाणा का बड़ा प्रहार: कुख्यात गैंगस्टर अमन भैंसवाल अमेरिका से निर्वासित, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिसाल

हिन्द जनपथ
चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने एक बार फिर संगठित अपराध के विरुद्ध अपनी निर्णायक क्षमता और वैश्विक स्तर पर ऑपरेशनल समन्वय का प्रदर्शन करते हुए वांछित गैंगस्टर अमन कुमार उर्फ अमन भैंसवाल को संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित कर भारत वापस लाने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। यह उपलब्धि हरियाणा पुलिस की अंतरराष्ट्रीय पहुंच, सतत निगरानी और रणनीतिक क्षमता की सशक्त मिसाल है। यह वर्ष 2025 से अब तक STF द्वारा किया गया छठा सफल निर्वासन तथा अमेरिका से किया गया दूसरा बड़ा ऑपरेशन है, जिसने हरियाणा पुलिस की अपराध–रोधी नीति को नई ताकत प्रदान की है।

डीजीपी अजय सिंघल की कड़ी चेतावनी

डीजीपी अजय सिंघल ने इस ऑपरेशन की सफलता पर अपराधियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि हरियाणा में अपराध के लिए अब कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। उन्होंने कहा, "जो अपराधी यह सोचते हैं कि सीमाओं के बाहर जाकर

या फर्जी पहचान बनाकर कानून से बच जाएंगे, वे यह समझ लें कि हरियाणा पुलिस की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। हर भगोड़ा, चाहे देश में हो या विदेश में, कानून के दायरे में लाया जाएगा। यह प्रदेश अपराधियों के लिए नहीं—कानून और व्यवस्था के लिए है। उनका यह संदेश संगठित अपराध के खिलाफ भविष्य में और भी सख्त कार्रवाई का संकेत देता है।

लंबे समय से सक्रिय अपराधी का नेटवर्क ध्वस्त

गौरतलब है कि अमन भैंसवाल हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में लंबे समय से फायरिंग, हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी और शस्त्र अधिनियम के मामलों में सक्रिय रहा है। वह स्वयं का गिरोह संचालित करता था और उसके नेटवर्क का प्रभाव सोनीपत, रोहतक, झज्जर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ था। उसके विरुद्ध हरियाणा और दिल्ली में कुल 10 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। घोषित अपराधी होने के बावजूद वह फर्जी पहचान के सहारे विदेश भागकर कानून से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन STF के निरंतर पीछा करने की नीति और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की गई समन्वित कार्रवाई के चलते उसकी यह चाल विफल हुई।

फर्जी पासपोर्ट और विदेश भागने की साजिश का खुलासा

जांच में स्पष्ट हुआ कि उसने पूर्वी दिल्ली पते के आधार पर एक फर्जी पहचान बनाकर अवैध रूप से पासपोर्ट प्राप्त किया और 20 जून 2024 को इसी पासपोर्ट के माध्यम से कुवैत भाग गया, बाद में अमेरिका पहुंचा। इस धोखाधड़ी के संबंध में भारतीय न्याय संहिता और पासपोर्ट अधिनियम के तहत गोहाना में मामला दर्ज किया गया। उसके विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर जारी हुआ, इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस प्राप्त किया गया और उसे घोषित अपराधी घोषित किया गया। यह सभी प्रक्रियाएं STF की कड़ी निगरानी, कानूनी सटीकता और समन्वित प्रयासों का परिणाम थीं।

अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ उच्चस्तरीय सहयोग

अमन भैंसवाल का अमेरिका से निर्वासन STF हरियाणा की उस व्यापक और आधुनिक रणनीति को दर्शाता है, जिसके तहत विदेशों में पनाह ले रहे भगोड़ों की लोकेशन, गतिविधियों और नेटवर्क का अध्ययन कर उन्हें कानून के दायरे में लाने के लिए निरंतर कार्रवाई की जा रही है। यह सफलता भारतीय एजेंसियों, इंटरपोल, अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों और राज्य पुलिस के बीच स्थापित भरोसे, तकनीकी क्षमता और तीव्र सूचना-साझाकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है।

STF की प्रतिबद्धता और भविष्य की रणनीति

अमन भैंसवाल का निर्वासन STF हरियाणा की उस दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता का प्रमाण है जिसमें अपराधी चाहे कहीं भी हों—न छुप सकते हैं, न कानून के शिकंजे से बच सकते हैं। यह उपलब्धि संगठित अपराध और भगोड़ों के खिलाफ चलाए जा रहे STF के आक्रामक व लक्षित अभियान की बड़ी सफलता है।

मुख्यमंत्री ने राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का कैलेंडर जारी किया

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का वार्षिक कैलेंडर-2026 जारी किया।इस अवसर पर बैंक के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को बैंक की विभिन्न गतिविधियों और योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।उन्होंने बताया कि विगत वर्ष में सरकार के निर्देशों के अनुसार पात्र लोगों को ऋण मुहैया करवाया गया।इस अवसर पर बैंक के प्रबन्ध निदेशक हरीश गज्जू और महाप्रबन्धक आर.एम. झमाल्टा उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सीमित के वर्ष-2026 का कैलेंडर जारी किया

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सीमित के कैलेंडर वर्ष-2026 का विमोचन किया।बैंक के अध्यक्ष राम चन्द्र पठानिया ने कैलेंडर का विमोचन करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया तथा कहा कि बैंक किसानों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रहा है ताकि उनके जीवन स्तर में आशातीत बदलाव लाया जा सके।

मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू को आज यहां वेल्फेयर एसोसिएशन ऑफ एनसीसी ऑफिसरज ऑफ हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 2.11 लाख रुपये का चेक भेंट किया।मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के योगदान विपरीत परिस्थितियों में पीड़ित लोगों की मदद के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साबित होते हैं।इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश कुमार, उपाध्यक्ष विवेकानंद, महासचिव अमरजीत, सदस्य रिपिन परमार, मेजर (प्रो.) लक्ष्मी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

स्वास्थ्य मंत्री 08 व 09 जनवरी को सोलन विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर

सोलन। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल 08 व 09 जनवरी, 2026 को सोलन विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर आ रहे हैं।डॉ. शांडिल 08 जनवरी, 2026 को दोपहर 12.30 बजे ग्राम पंचायत तोप की बेड़ में मनलोग से चौरा मार्ग की आधारशिला रखेंगे।स्वास्थ्य मंत्री तदोपरांत ग्राम पंचायत तोप की बेड़ के मनलोग में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री 09 जनवरी, 2026 को सोलन में लोगों की समस्याएं सुनेंगे।

एसजेवीएन ने हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष को 10 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की

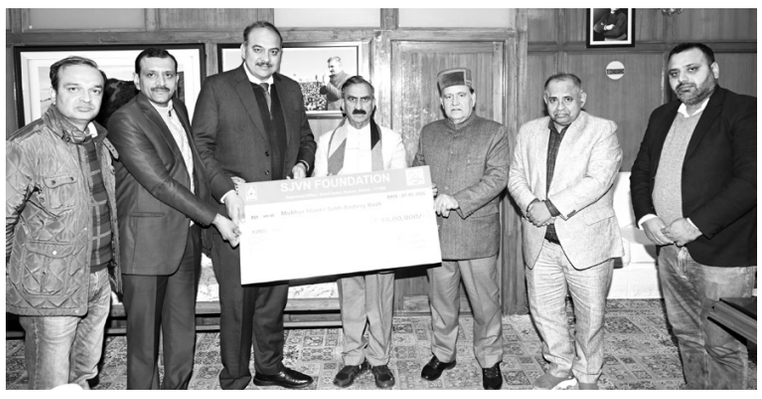

शिमला। श्री भूपेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,एसजेवीएन ने अवगत कराया कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत एसजेवीएन ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष को ?10 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह चेक हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया और प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री संजय सूद की उपस्थिति में, श्री विकास मारवाह, परियोजना प्रमुख, रामपुर जल विद्युत स्टेशन तथा श्री विवेक शर्मा, परियोजना प्रमुख, लूहरी जल विद्युत परियोजना (चरण-द्व) द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री अजय कुमार शर्मा, निदेशक (कार्मिक), एसजेवीएन एवं अध्यक्ष, एसजेवीएन फाउंडेशन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना राज्य भर में अनाथ, बेसहारा एवं समर्पित बच्चों की समग्र देखभाल, संरक्षण तथा दीर्घकालिक सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। एसजेवीएन फाउंडेशन द्वारा प्रदान की गई यह सहायता योजना से लाभार्थी बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण, आवास, कौशल विकास एवं समग्र पुनर्वास से संबंधित भावी आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देगी।

एसजेवीएन फाउंडेशन, एसजेवीएन का पंजीकृत ट्रस्ट है, जो कंपनी की सीएसआर एवं सततशील पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पारदर्शी निगरानी को सुनिश्चित करता है। अपनी सीएसआर रूपरेखा के अंतर्गत, एसजेवीएन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा एवं कौशल विकास, संरचना विकास, आपदा सहायता, सतत विकास तथा संस्कृति एवं खेलों के संवर्धन एवं संरक्षण से संबंधित विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए प्रतिबद्ध है।

जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित

अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने पर दिया जोर

धर्मशाला। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज उपायुक्त कार्यालय स्थित एनआईसी सभागार में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु और गंभीर चोटों की संख्या को कम करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों, ब्लैक स्पॉट्स की पहचान, जन-जागरूकता अभियानों, राहत एवं बचाव व्यवस्था तथा राह-वीर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई।

अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण मानवीय भूल, ओवर-स्पीडिंग, नशे की हालत में वाहन चलाना, खतरनाक ओवरटेकिंग तथा यातायात नियमों की अनदेखी है। लगभग 93 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं इन्हीं कारणों से हो रही हैं, जबकि 45 से 50 प्रतिशत दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों पर घटित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 118 ब्लैक स्पाट्स चिन्हित किए जा चुके हैं। इनकी पहचान, नियमित मॉनिटरिंग और सुधार के लिए उप-मंडल स्तर पर समितियों का गठन किया गया है, जिनमें पुलिस और लोक निर्माण विभाग की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर शीघ्र एवं प्रभावी सुधारात्मक कार्य किए जाएं, ताकि दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

अतिरिक्त उपायुक्त ने राह-वीर योजना की जानकारी देते हुए बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने वाले नागरिक को सम्मानित किया जाता है। उन्होंने बताया कि राह-वीर को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी सम्मानित किया जाएगा, जिससे समाज में मानवता और सहायता की भावना को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत सहायता करने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये तक का नकद पुरस्कार दिया जाता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर चयनित राह-वीर को एक लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए जन-जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए एनजीओ के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे तथा स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अतिरिक्त उपायुक्त ने ड्राइवरों की आई-टेस्टिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी चालक की अस्वस्थता दुर्घटना का कारण बन सकती है। विशेष रूप से स्कूल बस चालकों की नियमित नेत्र जांच सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि जिले में विभिन्न स्कूलों में कुल 1784 स्कूल बसें संचालित हो रही हैं, जिनमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे यात्रा करते हैं।

उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के पालन को सख्ती से लागू किया जाएगा। अस्पतालों और स्कूलों के आसपास सुरक्षित पैदल क्रॉसिंग विकसित की जाएंगी, ताकि बच्चों, मरीजों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि दुर्घटना के बाद त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए, ताकि मृत्यु दर को न्यूनतम किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में शून्य मृत्यु दर प्राप्त करना है, जिसके लिए सभी विभागों के साथ-साथ आम जनता की सहभागिता भी अनिवार्य है।

इस अवसर पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनीष सोनी ने सड़क सुरक्षा से संबंधित पहलुओं की जानकारी दी और सड़क सुरक्षा के विभिन्न आंकड़े प्रस्तुत किए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजिंदर जरियाल, एसडीएम मोहित रत्न, संयुक्त आयुक्त शहरी विकास सुरेन्द्र कटोच, उप-निदेशक शिक्षा अजय संब्याल, डॉ. महिमा कौल, आरएम एचआरटीसी साहिल कपूर, अध्यक्ष सक्षम सोसायटी सुनील कौल, जिला पंचायत अधिकारी विक्रम ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी एसडीएम, एनएचएआई तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए सीनियर रेजिडेंटशिप पॉलिसी बनाई जाएगी: मुख्यमंत्री

- चिकित्सा महाविद्यालयों में एमडी-एमएस के नए विषय होंगे शुरू

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए सीनियर रेजिडेंटशिप पॉलिसी बनाई जाएगी। इस पॉलिसी के तहत सीनियर रेजिडेंट के पदों का युक्तिकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीनियर रेजिडेंटशिप में जीडीओ का कोटा 66 प्रतिशत किया जाएगा। अभी इसका अनुपात जीडीओ व सीधी भर्ती द्वारा पचास-पचास प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा, नाहन, हमीरपुर व नेरचौक में नए विषयों में एमडी व एमएस करवाई जाएगी। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत संरचना और सुदृढ़ होगी। ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि जो डीएम और एमसीएच सुपरस्पेशलिस्ट फील्ड में हैं उन्हें चिकित्सा महाविद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में उच्च तकनीकयुक्त स्टेट-ऑफ-द-आर्ट आईसीयू स्थापित किये जाएंगे।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र नियुक्त किये जाएंगे, जिसमें से 500 चिकित्सा महाविद्यालयों और 500 अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात किये जाएंगे। इसके लिए प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट हमीरपुर जिला से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रोगी मित्र की कार्यप्रणाली के लिए विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण में रोगी मित्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तैनात किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि चमियाणा अस्पताल, चिकित्सा महाविद्यालय टांडा व आईजीएमसी शिमला में भी पायलट आधार पर 70 वर्ष से अधिक आयु के मरीजों की मदद के लिए रोगी मित्र तैनात किये जाएंगे। इन संस्थानों में रोगी मित्र कांऊटर भी स्थापित किये जाएंगे। ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय की विभिन्न ओपीडी में मरीजों से सम्बन्धित विभिन्न डेटा दर्ज करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर भी तैनात किये जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा को सशक्त करने के लिए नवोन्मेषी उपायों के साथ-साथ दीर्घकालिक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ताकि इस क्षेत्र में प्रदेश, देश का अग्रणी राज्य बने। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकर (नवीनीकरण, डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस) गोकुल बुटेल, सचिव स्वास्थ्य प्रियंका बासु इंगटी, विशेष सचिव स्वास्थ्य अश्वनी शर्मा एवं जितेन्द्र सांजटा, निदेशक स्वास्थ्य शिक्षा डॉ. राकेश शर्मा, निदेशक स्वास्थ्य गोपाल बेरी और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राजेश धर्माणी ने की रेरा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता

शिमला। नगर नियोजन एवं आवास मंत्री राजेश धर्माणी ने आज यहां हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी आथॉरिटी (रेरा) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पहाड़ी राज्य हिमाचल की भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य में सुनियोजित निर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में लोगों को किफ़ायती, पर्यावरण अनुकूल और बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हो रहा है।

उन्होंने कहा कि रेरा रियल एस्टेट में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और संपत्ति संबंधी विवादों के निवारण में अहम भूमिका निभाता है। रेरा द्वारा संपत्ति के ख़रीददारों को परियोजनाओं संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाने के अलावा पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तकनीक का सर्वोत्तम उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में रेरा में 269 रियल एस्टेट परियोजनाएं और 159 रियल एस्टेट एजेंट पंजीकृत हैं। रेरा द्वारा 194 शिकायतों में से 144 का निवारण किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वेब-एक्स के माध्यम से ऑनलाइन शिकायतों की सुनवाई सुनिश्चित की गई है। ट्रैज़री में रेरा द्वारा 1.2 करोड़ रुपये जमा करावाए गए है। इसके अतिरिक्त लगभग 7 करोड़ रुपये घर ख़रीददारों को वापिस किए गए है।

उन्होंने कहा कि रेरा घर ख़रीददारों को सशक्त बनाने और परियोजनाओं के समयबद्ध निष्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि डेवलपर को परियोजना संबंधी प्लान, ले-आउट और निर्माण में उपयुक्त होने वाली सामग्री का विवरण देना आवश्यक है। इससे ख़रीददारों को बेहतर परियोजनाएं उपलब्ध होगी। निष्पादन एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं से संबधित जियो टैग फोटोग्राफ और वीडियो के माध्यम से संबधित विभाग द्वारा परियोजनाओं में गुणवतापूर्ण निर्माण सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं की शिकायतों के निवारण और परियोजनाओं संबधित मामलों के समाधान कर रेरा ख़रीददारों और डेवलपर के बीच विश्वास को और मजबूत कर रहा है। बैठक में बिल्डिंग सेफ्टी काउन्सिल के गठन के संबध में भी चर्चा की गई। बैठक में रेरा के सदस्य विदुर मेहता, अध्यक्ष आर. डी. धीमान और अन्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

एसजेवीएन ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष में 10 लाख रुपये का अंशदान किया

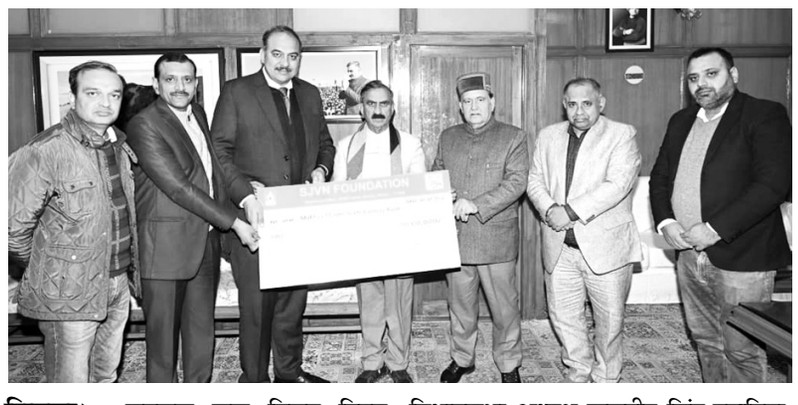

शिमला। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए 10 लाख रुपये का चेक भेंट किया। एसजेवीएन ने यह धनराशि निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत प्रदान की। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन भूपेंद्र गुप्ता, निदेशक (कार्मिक), एसजेवीएन अजय कुमार शर्मा, परियोजना प्रमुख, रामपुर जल विद्युत स्टेशन विकास मारवाह, परियोजना प्रमुख, लुहरी जल विद्युत परियोजना (स्टेज-1) विवेक शर्मा तथा पीसीसीएफ संजय सूद भी उपस्थित थे।

रोस्टर और बैकलॉग रिक्तियों के मुद्दे शीघ्र हल करें: निदेशक

शिमला। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण विभाग (ईसोमसा) (मैड्डै।) द्वारा आज यहां दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडीज) से संबंधित मुद्दों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विशेष रूप से दृष्टिबाधित संघ द्वारा उठाई गई मांगों सहित दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई।

दिव्यांगजनों सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए, निदेशक सुमित खीमटा ने बताया कि अब तक केवल पशुपालन और मुद्रण एवं लेखा विभाग ने ही बैकलॉग पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किए हैं। उन्होंने शेष विभागों से दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित शेष पदों को शीघ्र भरने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया, 'स्कूल शिक्षा विभाग ने दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित जेबीटी पदों के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 119 जेबीटी पद भरे गए हैं, जिनमें 50 दृष्टिबाधित, 49 आर्थोपेडिक रूप से अक्षम, 11 श्रवणबाधित, 8 बहु-दिव्यांगता वाले तथा 1 बौद्धिक रूप से अक्षम के लिए हैं।'

उन्होंने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 94 टीजीटी पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें 26 दृष्टिबाधित, 22 श्रवणबाधित, 13 बौद्धिक रूप से अक्षम या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले तथा 10 बहु-दिव्यांगता वाले के लिए आरक्षित हैं।

बैठक में एचआरटीसी बसों में निःशुल्क यात्रा हेतु अनिवार्य हिम बस कार्ड की आवश्यकता के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। निदेशक ने कहा कि दिव्यांगजनों को बस कार्ड प्राप्त करने में सहायता हेतु विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि, दृष्टिबाधित संघ ने मांग की है कि दिव्यांगजनों के लिए एचआरटीसी बसों में निःशुल्क यात्रा हेतु हिम बस कार्ड अनिवार्य न किया जाए तथा उन्हें छूट दी जाए। संघ ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

अन्य मुद्दों में दिव्यांगजनों हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विकलांगता राहत भत्ता (डीआरए) बढ़ाना, दिव्यांगजनों हेतु स्वतंत्र राज्य आयुक्त की नियुक्ति, सहारा पेंशन योजना का कार्यान्वयन, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दृष्टिबाधित व्यक्तियों को बिना शर्त आवास प्रदान करना तथा दिव्यांगजन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करना शामिल थे। दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विकलांगता राहत भत्ता (डीआरए) बढ़ाना तथा सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि नीतिगत मामले हैं, जिन पर राज्य सरकार निर्णय लेगी। दृष्टिबाधित संघ ने बताया कि सहारा पेंशन योजना का लाभ पिछले छह माह से लाभार्थियों को नहीं मिला है, मामले को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भेजा गया है।

दृष्टिबाधित संघ के अध्यक्ष शोभू राम ने बैठक आयोजित करने तथा राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग पदों को भरने की प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए अध्यक्ष का धन्यवाद किया। उन्होंने अधिकारियों से प्रक्रिया को तेज़ गति प्रदान करने का आग्रह किया ताकि बैकलॉग रिक्तियां शीघ्र भरी जा सकें।

बैठक में नियंत्रक (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) प्रभा राजीव, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, दिव्यांगजन संघ के सदस्य पीडी भारद्वाज तथा दृष्टिबाधित संघ के शिशुपाल मेहता और निखिल मेहता शामिल थे।

स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी के जन्मोत्सव पर गरली में शांति पूजन एवं पाठ का आयोजन

राज्यपाल शुक्ल ने की कार्यक्रम में सहभागिता

शिमला। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजय करोल के पैतृक गांव गरली, जिला कांगड़ा में उनकी स्वर्गीय माता श्रीमती निर्मला देवी के जन्मोत्सव के अवसर पर शांति पूजन एवं पाठ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल ने सहभागिता की। लेडी गवर्नर श्रीमती जानकी शुक्ल भी इस अवसर पर उपस्थित रहीं।

इस अवसर पर राज्यपाल ने माता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मां द्वारा दी गई शिक्षाएं जीवन का आधार होती हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मां की सेवा करता है और उनके संस्कारों को आत्मसात करता है, वह जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। उन्होंने यह भी कहा कि संतों और महापुरुषों के वचनों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वे जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं और मानव को सद्मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देते हैं। शांति पूजन एवं पाठ के माध्यम से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई।

आवश्यक सूचना

पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन में प्रकाशित किसी उत्पाद या सेवा के बारे में पूरी तरह जांच पड़ताल कर लें। यह समाचार पत्र उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किये गये दावे उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता। समाचार पत्र उपरोक्त विज्ञापनों के बारे में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

RNI NO: HARHIN/2002/08034, Postal Regd No. HR/AB/54/23-25, स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक एकान्ति राय गर्ग द्वारा जनपथ पब्लिशर्स, बूथ नं.: 437-पी (बी.पी.पेट्रोल पंप के पीछे) सेक्टर-8, पंचकूला से प्रकाशित। **सम्पादक:- एकान्ति रॉय गर्ग,** मुख्य कार्यालय: बूथ नं: 437-पी (बी.पी.पेट्रोल पंप के पीछे) सेक्टर-8 पंचकूला-134109(हरियाणा)। मो.: 9915606900, email : hindjanpath@gmail.com, argarg1610@gmail.com ।

न्यूज डायरी

आइकॉनिक कैटेगरी लीडर ब्लेंडर्स प्राइड ने ज़ेनिथ ब्लैक एडिशन के लॉन्च की घोषणा की

पानीपत। भारत के प्रीमियम व्हिस्की सेगमेंट में अग्रणी ब्रांड ब्लेंडर्स प्राइड ने ब्लेंडर्स प्राइड ज़ेनिथ ब्लैक एडिशन के लॉन्च की घोषणा की है। यह एक लिमिटेड-एडिशन पेशकश है, जो बोल्ड ब्लैक सौंदर्य को ब्लेंडर्स प्राइड के आइकॉनिक ब्लेंड के साथ जोड़कर एक वास्तव में विशिष्ट अनुभव प्रस्तुतकरती है।ऊँचे स्तर की लग्ज़री और विशिष्टता को दर्शाने वाले आकर्षक ब्लैक डिज़ाइन में पैक किया गया ज़ेनिथ ब्लैक एडिशन चुनिंदा व्हिस्की प्रेमियों के लिए बारीकी से तैयार किया गया है—वन इन अ मिलियन के लिए। केवल दस लाख बोतलों की उपलब्धता के साथ, यह एडिशन जितना रेयर है उतना ही रिफाइंड भी है।लग्ज़री की दुनिया में ब्लैक सिर्फ़ एक रंग से कहीं अधिक है—यह एक एटीट्यूड, सोफिस्टिकेशन और पॉवर का प्रतीक है। लंबे समय से ब्लेंडर्स प्राइड से जुड़ा ब्लैक अब एक इनोवेटिव डिज़ाइन एक्सप्रेशन के रूप में केंद्र में आता है, जो प्रीमियम व्हिस्की के मानकों को रिडिफाइन करता है। यह केवल नई पैकेजिंग नहीं

है; यह उन लोगों के लिए स्टाइल की एक बोल्ड एक्सप्रेशन है जो ट्रेंड्स का पीछा नहीं करते बल्कि उन्हें बनाते हैं।पर्नोड रिकार्ड इंडिया की सीएमओ, देबाश्री दासगुप्ता ने कहा, "ब्लेंडर्स प्राइड भारत में प्रीमियम व्हिस्की के मानकों को लगातार नया रूप देता रहा है। ज़ेनिथ ब्लैक एडिशन का लॉन्च ब्रांड का अब तक का सबसे रिफाइंड एक्सप्रेशन है—एक ऐसा इवोल्यूशन जो इसकी स्थायी विरासत को एक बोल्ड नई डिज़ाइन लैंग्वेज में बदलता है। इस वर्ष, ब्लेंडर्स प्राइड अपने मूल मूल्यों को एक ऐसे सौंदर्य के माध्यम से जीवंत कर रहा है जो आकांक्षा, विशिष्टता और कारीगरी का उत्सव मनाता है। केवल दस लाख बोतलों तक सीमित ज़ेनिथ ब्लैक एडिशन उन व्यक्तियों के लिए बनाया गया है जो केवल उत्कृष्टता की प्रशंसा नहीं करते—वे उसे जीते हैं। ब्लेंडर्स प्राइड ज़ेनिथ ब्लैक एडिशन उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो असाधारण की तलाश में रहते हैं—यह एक उन्नत अनुभव है, जो बिना किसी समझौते की गुणवत्ता को किसी सचमुच विशेष चीज़ के स्वामित्व की विशिष्टता के साथ जोड़ता है।पैन-इंडिया लॉन्च की योजना के तहत, ब्लेंडर्स प्राइड ज़ेनिथ ब्लैक एडिशन फिलहाल केवल चुनिंदा एक्सक्लूसिव स्टोर्स में उपलब्ध है।

'युद्ध नशों विरुद्ध': 312वें दिन पंजाब पुलिस ने 6.2 किलोग्राम हेरोइन सहित 107 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

हिन्द जनपथ
चंडीगढ़ (ब्यूरो)। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य से नशों के पूर्ण उन्मूलन के लिए चलाई जा रही मुहिम "युद्ध नशों विरुद्ध" के लगातार 312वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 296 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान राज्य भर में 107 नशा तस्करों को गिरफ्तार करते हुए 82 एफआईआर दर्ज की गईं। इसके साथ ही 312 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या अब 43,544 हो गई है।

छापेमारी के परिणामस्वरूप गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 6.2 किलोग्राम हेरोइन, 7 किलोग्राम भुक्की, 496 नशीली गोलियाँ/कैप्सूल तथा 34,820 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ इस युद्ध की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है।

64 राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में 800 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 100 से ज्यादा पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में 296 स्थानों पर छापेमारी की। इस दिनभर चले अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 300 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की।

राज्य से नशों के उन्मूलन के लिए राज्य सरकार ने तीन-स्तरीय रणनीति—प्रवर्तन (एनफोर्समेंट), नशा मुक्ति (डी-एडिक्शन) और रोकथाम (प्रिवेंशन)—लागू की है। इसी के तहत पंजाब पुलिस ने आज 'नशा मुक्ति' पहल के अंतर्गत 41 व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार के लिए सहमत किया है।

पिछले कुछ महीनों में 1000 से अधिक कर्मचारियों को किया गया नियमित : लाल चंद कटारूचक

हिन्द जनपथ
चंडीगढ़ (ब्यूरो)।

वन एवं वन्यजीव सुरक्षा विभाग ने पिछले 7 महीनों के दौरान 1000 से अधिक कर्मचारियों की सेवाएँ नियमित की हैं तथा वर्ष 2023 में बनाई गई नीति के तहत 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके 519 अन्य वरिष्ठ कर्मचारियों—जो आयु और शैक्षणिक योग्यता की शर्तें पूरी नहीं करते—को नियमित करने का प्रस्ताव वित्त, कार्मिक और कानूनी सलाहकार विभाग को भेजा गया है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व से प्रेरणा लेते हुए वन विभाग अपने कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह जानकारी आज वन एवं वन्यजीव सुरक्षा मंत्री लाल चंद कटारूचक ने वन परिसर में फॉरेस्ट वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान दी।

यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा पिछले वर्ष 30 जुलाई को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के वेतन जारी करने की माँग के संबंध में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि इस संबंध में एकीकृत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (आई.एस.आर.एम.एस.) की आईडी अपडेट कर दी गई हैं और शीघ्र ही वेतन जारी कर दिए जाएंगे।

सीमा सुरक्षा बल द्वारा सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक अलंकरण समारोह का आयोजन

हिन्द जनपथ
मोहाली(ब्यूरो)। सीमा सुरक्षा बल की पश्चिमी कमान ने मुख्यालय, सीमा सुरक्षा बल, पश्चिमी कमान, लखनौर कैम्पस, मोहाली (पंजाब) में आज सीमा सुरक्षा बल कर्मियों को उनकी सराहनीय सेवा हेतु पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए पदक अलंकरण समारोह का आयोजन किया।

इस अवसर पर पंजाब के माननीय राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में और ट्राइसिटी मोहाली, चण्डीगढ, पंचकुला में पदस्थ/कार्यरत सिविल एवं पुलिस प्रशासन के अन्य विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। समारोह आयोजन के दौरान, कुल 24 कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य व्यक्तियों

का स्वागत करते हुए, श्री सतीश एस खण्डारे, भारतीय पुलिस सेवा, अपर महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, पश्चिमी कमान ने दर्शकों को सीमा सुरक्षा बल के गौरवशाली अतीत के बारे में अवगत कराया और उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।

सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक उन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस के कर्मियों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने 18 से अधिक वर्षों की सराहनीयएवं उत्कृष्ट सेवाएं देश को समर्पित की हैं। यह चौथा अवसर है, जब यह समारोह द सिटी ब्यूटीफुल 'चण्डीगढ' में माननीय राज्यपाल पंजाब एवं प्रशासक चण्डीगढ की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।

दर्शकों को संबोधित करते हुए पंजाब के माननीय राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया जी ने

शांति और युद्ध काल के दौरान भारत-पाक और भारत-बांग्लादेश सीमा को प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखने में बीएसएफ अधिकारियों और कर्मियों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीएसएफ न केवल देश की सीमाओं की ही रक्षा करती है बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा को भी बनाए रखने में पूर्णतह सक्षम है। साथ ही ऑपरेशन सिन्दूर में बी एस एफ की सक्रिय भूमिका तथा जम्मू व पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव राहत अभियान के बारे में भी विस्तार से बताया।

समारोह के अंत में मुख्य अतिथि ने सभी पदक प्राप्तकर्ताओं को बधाई देते हुए उन्हें और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दीं।

सवाड़ा-सैदपुर-गिदड़पुर-चंडियाला मार्ग के नवीनीकरण पर खर्च होंगे 2.92 करोड़: विधायक कुलवंत सिंह ने किया उद्घाटन

इलाके के विकास को मिलेगी नई रफ्तार: विधायक कुलवंत सिंह

हिन्द जनपथ
मोहाली(ब्यूरो)। विधायक कुलवंत सिंह द्वारा आज इलाका निवासियों की लंबे समय से लटकी आ रही मांग को पूरा करते हुए सवाड़ा-सैदपुर-गिदड़पुर-चंडियाला मार्ग को चौड़ा करने और इसके नवीनीकरण के कार्यों का औपचारिक उद्घाटन किया गया।

इस अवसर पर जनसमूह को संबोधित करते हुए विधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार इलाके के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इस महत्वपूर्ण मार्ग की कुल लंबाई 5.09 किलोमीटर है, जिसे अब 10 फीट से बढ़ाकर 18 फीट चौड़ा किया जा रहा है ताकि यातायात में आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सके।

इस प्रोजेक्ट की तकनीकी बारीकियां साझा करते हुए उन्होंने बताया कि इस पूरे कार्य पर लगभग 2 करोड़ 92 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 2.75 करोड़ रुपये सड़क बनाने और बाकी 17 लाख रुपये सड़क के पांच साल के रखरखाव पर खर्च होंगे। गौरतलब है कि इससे पहले यह सड़क साल 2017 में बनी थी और लंबे समय से मरम्मत के इंतज़ार में थी। इस सड़क के लगभग 1 किलोमीटर हिस्से को पेवर ब्लॉक और बाकी

के 4 किलोमीटर हिस्से को लुक से बनाया जाएगा। अब इस सड़क को बनाने का काम अगले 6 महीनों के भीतर मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिससे राहगीरों को बड़ी राहत मिलेगी।

विधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पिछले तीन वर्षों से भी अधिक समय से पंजाब के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया जा रहा है और आने वाले दिनों में विकास की रफ्तार और तेज होने वाली है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों की बुनियादी सुविधाएं पूरी करने के साथ ही पिछले लंबे समय से लटके मसलों का स्थायी समाधान किया जा रहा है, जिसके कारण अब विपक्षी पार्टियों के नेताओं के पास आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा है।

विधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता और बड़े पदाधिकारी लगातार आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं; यह सब आम आदमी पार्टी की सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी परिवार में वृद्धि कर रहे हैं। इस मौके पर सरपंच गुरप्रीत कौर पत्नी नरिंदर सिंह सोनी, पूर्व सरपंच सुरजीत सिंह, अमनदीप कौर पत्नी परमिंदर सिंह, पूर्व सरपंच गुरमेल सिंह, कुलदीप कौर प्रभारी महिला विंग और पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के एक्सियन विवेक दुरेजा विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर समस्त पंचायतों और ग्रामीणों ने विधायक कुलवंत सिंह का धन्यवाद करते हुए कहा कि सड़क चौड़ी होने से इलाके की नुहार बदलेगी और हादसों का खतरा भी कम होगा।

मान सरकार ने दशकों पुराने पैटर्न को तोड़ा, सरकारी अस्पताल में किया पहला लिवर ट्रांसप्लांट

हिन्द जनपथ
चंडीगढ़ (ब्यूरो)। पंजाब सरकार ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (पी.आई.एल.बी.एस.), एस.ए.एस. नगर में प्रदेश में पहला सफल लिवर ट्रांसप्लांट करवाकर एक निर्णायक प्रशासनिक मील का पत्थर स्थापित किया है। आजादी के बाद पहली बार, पंजाब सरकार द्वारा सबसे जटिल और महंगी जीवन-रक्षक चिकित्सा प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया को प्रदेश की सरकारी संस्था में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया गया है जो पहले महानगरों के निजी अस्पतालों तक ही सीमित थी। यह उपलब्धि कोई अकेली चिकित्सा उपलब्धि नहीं है। यह दृढ़ इरादे को बयान करती है। यह उपलब्धि दशकों की उपेक्षा से स्पष्ट राहत प्रदान करती है, जिस तहत पिछली प्रदेश सरकारों ने महत्वपूर्ण तृतीय स्तर की स्वास्थ्य देखभाल को दिल्ली, मुंबई या चेन्नई तक सीमित रखा और जिससे पंजाब के मरीजों को भारी वित्तीय और भावनात्मक खर्च झेलने पड़े। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में प्रदेश निर्भरता से क्षमता की ओर बढ़ा है।

जनता स्वास्थ्य देखभाल प्रदेश की जिम्मेदारी, न कि अमीरों के लिए विशेष अधिकार

पी.आई.एल.बी.एस. में लिवर ट्रांसप्लांट सेवाएं शुरू करना स्वास्थ्य देखभाल प्रति मान सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है। जिसमें नागरिकों को निजी अस्पतालों की ओर जाने के लिए मजबूर करने की बजाय मजबूत सरकारी संस्थाओं का निर्माण करना शामिल है। उन्नत देखभाल सेवाओं को अब अमीरों के लिए विशेष अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि सभी नागरिकों प्रति प्रदेश की जिम्मेदारी माना जाता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, 'मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी अगुवाई के तहत, पंजाब सरकार द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जा रहा है जो विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल तक आम नागरिक की आसान पहुंच को सुनिश्चित करती हैं।

गुरुओं का अपमान AAP की सिख आस्था के प्रति गहरी घोर अनादर एवं द्वेषपूर्ण है: चुग

हिन्द जनपथ
चंडीगढ़ (ब्यूरो)। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कहा कि आम आदमी पार्टी का नेतृत्व लगातार सिख धर्म की आस्था, परम्पराओं और मर्यादाओं के विरुद्ध आचरण करता हुआ सामने आ रहा है।

चुग ने कहा कि पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा सिख धर्म के सिद्धांतों और पवित्र परम्पराओं को लेकर दिए गए बयान तथा सामने आए वीडियो सिख समाज की भावनाओं को गहराई से आहत करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सिखों के पवित्र गोलक को लेकर भगवंत मान की टिप्पणी न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि यह सिख मर्यादाओं के प्रति AAP की असंवेदनशील और अपमानजनक सोच को उजागर करती है।

चुग ने कहा कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि AAP नेतृत्व का एक लगातार दोहराया जाने वाला व्यवहार है, जिसमें सिख आस्था और धार्मिक मूल्यों को राजनीतिक सुविधा के अनुसार निशाना बनाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में चल रहे इन घटनाक्रमों के बीच दिल्ली विधानसभा में सिख गुरुओं के संदर्भ में जो हुआ, उसने AAP की मानसिकता को और स्पष्ट कर दिया है। तरुण चुग ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में अतीशी का व्यवहार सिख गुरुओं के प्रति घोर अपमानजनक है और इसने हर नैतिक और संवैधानिक मर्यादा को लांघ दिया है।

पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा पंजाब में 300 करोड़ रुपये की लागत से एडहेसिव और वॉटरप्रूफिंग निर्माण सुविधा स्थापित की जाएगी: संजीव अरोड़ा

हिन्द जनपथ
चंडीगढ़ (ब्यूरो)। पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, बिजली तथा प्रवासी भारतीय मामलों के कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने आज घोषणा की कि एडहेसिव तथा निर्माण से संबंधित रसायनों के उत्पादन में अग्रणी कंपनी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा पंजाब में 300 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ एक नई निर्माण सुविधा स्थापित की जाएगी।

यह प्रस्तावित परियोजना गांव माजरी फकीरां तथा गांव सोहणे माजरा, उप-तहसील घनौर, राजपुरा, जिला पटियाला में 31 एकड़ भूमि पर स्थापित की जाएगी।

श्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि यह सुविधा जल-आधारित एडहेसिव उत्पादों तथा वॉटरप्रूफिंग उत्पादों के मिश्रण और ब्लेंडिंग पर केंद्रित होगी। इसकी कुल प्रस्तावित उत्पादन क्षमता वार्षिक 2,00,000 मीट्रिक टन होगी, जिसमें 1,40,000 मीट्रिक टन जल-आधारित एडहेसिव उत्पाद तथा 60,000 मीट्रिक टन वॉटरप्रूफिंग उत्पाद शामिल होंगे। यह सुविधा मुख्य रूप से घरेलू बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करेगी तथा भविष्य में आसपास के बाजारों में निर्यात की

संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

इस परियोजना से उत्पन्न होने वाली रोजगार संभावनाओं को रेखांकित करते हुए मंत्री ने कहा कि इस परियोजना से लगभग 300 रोजगार अवसर सृजित होने की उम्मीद है, जिनमें कुशल, अर्ध-कुशल और पर्यवेक्षण श्रेणियों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नौकरियां शामिल होंगी। उन्होंने आगे कहा कि यह सुविधा सर्वोत्तम औद्योगिक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक उपकरणों, उपयोगिताओं तथा अनुकूल वातावरण के साथ स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (ईएचएस) प्रणालियों से युक्त होकर विकसित की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी और यह भारत में उपभोक्ता तथा विशेष रसायनों के उत्पादन में एक अग्रणी कंपनी एवं मार्केट लीडर है। कंपनी एडहेसिव और सीलेंट, निर्माण से संबंधित रसायन, औद्योगिक रेज़िन, पिगमेंट तथा कला एवं शिल्प सामग्री के निर्माण में अग्रणी है। इसका प्रमुख ब्रांड 'फेविकोल' देश के सबसे विश्वसनीय ब्रांडों में से एक है।

श्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि उत्तर भारत में अपने निर्माण आधार को सुदृढ़ करने और बढ़ती क्षेत्रीय मांग को पूरा करने की रणनीति के तहत पिडिलाइट द्वारा पंजाब में यह प्रस्तावित सुविधा स्थापित की जा रही है। इस परियोजना का वित्तपोषण पूरी तरह आंतरिक संसाधनों के माध्यम से किया जाएगा और इसे दिसंबर 2027 तक वाणिज्यिक उत्पादन के लिए चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रगति पोर्टल: भारत की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना को तेज़ी से आगे बढ़ाने वाला एक गेम चेंजर

लेखक : श्री आर.के जैन, पूर्व एमडी, डीएफसीसीआईएल

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) परियोजना आज़ादी के बाद शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी रेल अवसंरचना योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य माल ढुलाई के लिए उच्च क्षमता और आधुनिक तकनीक से लैस विशेष रेल कॉरिडोर तैयार करना है।

इस परियोजना के माध्यम से भारतीय रेल तेज़, सुरक्षित, भरोसेमंद और कम लागत वाली लॉजिस्टिक सेवाएं देकर माल परिवहन के क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी दोबारा बढ़ाना चाहती है। साथ ही, इस परियोजना से मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्कों के विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और पूरी आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार होगा।

करीब 1.2 लाख करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत और 2843 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के दो मुख्य हिस्से हैं:

पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर(ईडीएफसी):

यह 1337 किलोमीटर लंबा है। यह कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना स्थित साहनेवाल से लेकर बिहार के सोननगर तक जाता है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों से होकर गुजरता है।

पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी):

यह 1506 किलोमीटर लंबा है। यह उत्तर प्रदेश के दादरी से लेकर मुंबई के पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) तक फैला हुआ है। यह हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर गुजरता है। कुल मिलाकर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) का मार्ग 7 राज्यों और 56 जिलों से होकर गुजरता है। यह जंगलों, वन्यजीव अभयारण्यों, मैंग्रोव क्षेत्रों और क्रीक इलाकों से भी होकर जाता है, जिससे इस परियोजना का निर्माण कार्य स्वाभाविक रूप से जटिल हो जाता है।

समय पर पूरा होने में आने वाली चुनौतियां

हालांकि इस परियोजना की शुरुआत 2008 में हुई थी, लेकिन कई बाधाओं के कारण कई वर्षों तक काम की गति धीमी रही। मुख्य चुनौतियां इस प्रकार थीं:

लगभग 11,000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण, जिसमें अवैध कब्जे और बने हुए ढांचों को हटाना शामिल था।

वन भूमि, वन्यजीव अभयारण्यों, मैंग्रोव क्षेत्रों, पेड़ों की कटाई और क्रीक (नाले) पार करने से जुड़े कानूनी अनुमतियां प्राप्त करना।

900 से अधिक लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने के लिए रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) का निर्माण, जिनके लिए संयुक्त नक्शा स्वीकृति और रास्तों के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक था।

हाई टेंशन बिजली लाइनों, गैस और तेल पाइपलाइनों को स्थानांतरित करना।

रक्षा विभाग, एनएचएआई, राज्य राजमार्ग प्राधिकरणों, सिंचाई विभाग से नहर पार करने की अनुमति और मिट्टी उधार लेने की स्वीकृति।

कोविड के बाद ठेकेदारों पर पड़ा आर्थिक दबाव, जिससे नकदी की कमी हुई।

निर्माण के लिए बिना किसी बाधा वाली भूमि उपलब्ध न होने से कार्य समय-सारिणी पर गंभीर असर पड़ा और परियोजना पर संभावित दावों का खतरा भी बढ़ गया।

प्रगति पोर्टल-निर्णायक मोड़

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से शुरू किया गया प्रगति पोर्टल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) परियोजना के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ। इस पोर्टल के माध्यम से डीएफसी के अधिकारियों ने लंबे समय से लंबित समस्याओं को पूरे दस्तावेज़ों के साथ अपलोड किया। प्रगति पोर्टल की सबसे बड़ी ताकत इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही थी। संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विभागों को यह साफ़ पता था कि कार्य की प्रगति पर सबसे ऊंचे स्तर पर, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी, निगरानी की जा रही है। जो मुद्दे वर्षों तक लगातार प्रयासों के बावजूद अटके रहे थे, वे कुछ ही हफ्तों में, और कई मामलों में तो कुछ दिनों के भीतर ही, सुलझा लिए गए। जहाँ तुरंत समाधान संभव नहीं था, वहाँ विभागों ने निश्चित समय-सीमा तय की और उसका सख्ती से पालन किया गया।

उत्तर रेलवे
ई–नीलामी सूचना

भारत के राष्ट्रपति की तरफ से वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक, उत्तर रेलवे अंबाला छवानी द्वारा मण्डल के निम्नलिखित स्टेशनों पर ठेके आवंटित करने हेतु ई–नीलामी रेलवे वेब साइट **www.ireps.gov.in** के माध्यम से बोली आमंत्रित की जा रही है। आवंटित की जाने वाले ठेको का विवरण निम्नलिखित है।

क्र. सं.	नीलामी काटलोग सं.	कार्य का विवरण	नीलामी तिथि व समय
1	UMB-Prkg-28-25	मलोट रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में कुल 955.75 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले व्यापक पार्किंग स्थल का आवंटन।	12.01.26
2		सरहिंद रेलवे स्टेशन पर 1745.93 वर्ग मीटर के पार्किंग क्षेत्र में सभी वाहनों (गैर-वाणिज्यिक और वाणिज्यिक) के लिए व्यापक पार्किंग सह प्रवेश नियंत्रण अधिकार "पिकअप/ड्रॉप" लेन (प्रवेश से निकास तक) का आवंटन।	12:00:00
3	UMB-Prkg-01-26	मालेरकोटला रेलवे स्टेशन के परिसंचार क्षेत्र में 1757.128 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल में फैले व्यापक पार्किंग स्थल का आवंटन (साइट प्लान के अनुसार)	21.01.26
4		अंबाला डिवीजन के कालका रेलवे स्टेशन पर स्थित सामान्य पार्किंग क्षेत्र के साथ–साथ सभी वाहनों (गैर–वाणिज्यिक और वाणिज्यिक) के लिए "पिकअप/ड्रॉप" लेन (प्रवेश से निकास तक) के लिए "पार्किंग सह प्रवेश नियंत्रण अधिकार" अनुबंध पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए किया गया है।	10:00:00

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 71/26

संपादकीय

रेयर अर्थ की दौड़ में दुनिया दांव पर

दुनियाभर में दर्जनों संघर्ष रुकवाने के सैकड़ों दावे कर चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ही वैश्विक तनाव को भड़का रहे हैं। वेनेजुएला के बाद अमेरिका की ओर से ग्रीनलैंड को लेकर जो मेसेज आया है, वह दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। इससे तो अंतरराष्ट्रीय कानून, यूएन चार्टर और देशों की संप्रभुता का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ट्रंप प्रशासन में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर की पत्नी केटी मिलर ने एक तस्वीर पोस्ट की। जिसमें ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे में दिखाया गया है। इसके साथ लिखा था जल्द। स्टीफन को ट्रंप के चहेते लोगों में गिना जाता है, जबकि केटी खुद भी ट्रंप के पहले कार्यकाल में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रह चुकी हैं। ऐसे में उनके ट्वीट पर डेनमार्क और ग्रीनलैंड की तरफ से स्वाभाविक ही कड़ी प्रतिक्रिया आई। किंगडम ऑफ डेनमार्क के तहत आने वाले ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की महत्वकांक्षा पुरानी है। वह कई मौकों पर खुलेआम कह चुके हैं कि उन्हें अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए। ऐसे में केटी मिलर की तरफ से आ रहे ऐसे आपत्तिजनक मेसेज उसी का नतीजा है। ट्रंप पूरी दुनिया को एक कारोबारी की नजर से देख रहे हैं। उन्हें वेनेजुएला चाहिए, क्योंकि वहां तेल के भंडार है और ग्रीनलैंड चाहिए, क्योंकि वहां रेयर अर्थ का खजाना है। यही एक चीज है, जिसने अमेरिका को चीन के साथ ट्रेड वॉर में टिकने नहीं दिया। पिछले साल जब ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया, तो चीन ने जवाब में रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोक दी थी। थक हारकर अमेरिका को वार्ता की मेज पर आना पड़ा। आज दुनिया की जरूरत का 90 प्रतिशत रेयर अर्थ चीन से आता है और अमेरिका की टेक-ऑटो-डिफेंस इंडस्ट्री इसकी मोहताज है। ट्रंप इसे लेकर चीन का दबदबा कम करना चाहते हैं, लेकिन चोट अपने साथियों को पहुंचा रहे हैं। दूसरी बार सत्ता संभालते ही उन्होंने पड़ोसी कनाडा को अमेरिका का एक राज्य बनाने की इच्छा जाहिर की थी। फिर यूरोप को लेकर नीतियां बदली। जिस डेनमार्क को लेकर उनका स्टाफ आक्रामकता दिखा रहा है, वह खुद नैटो का सदस्य है और अमेरिका की जिम्मेदारी है उसकी सुरक्षा करना।

वेनेजुएला संकट

अमेरिकी निरंकुशता और वैश्विक कानूनों का हनन

दरअसल, वैश्विक कूटनीति के जानकारों का मानना है कि वेनेजुएला के मामले में अमेरिका की असली चिंता न लोकतंत्र है और न ही मानवाधिकार, बल्कि वहां के विशाल तेल भंडार हैं। वेनेजुएला विश्व के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक पर बैठा देश है और ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण की अमेरिकी भूख कोई नई बात नहीं है। वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था वास्तव में नियम-कानूनों से संचालित होती है या फिर ताकतवर राष्ट्रों की इच्छा ही वैश्विक न्याय का नया मानदंड बन चुकी है।

(ललित गर्ग)

दरअसल, वैश्विक कूटनीति के जानकारों का मानना है कि वेनेजुएला के मामले में अमेरिका की असली चिंता न लोकतंत्र है और न ही मानवाधिकार, बल्कि वहां के विशाल तेल भंडार हैं। वेनेजुएला विश्व के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक पर बैठा देश है और ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण की अमेरिकी भूख कोई नई बात नहीं है। वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था वास्तव में नियम-कानूनों से संचालित होती है या फिर ताकतवर राष्ट्रों की इच्छा ही वैश्विक न्याय का नया मानदंड बन चुकी है। निश्चित तौर पर वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला महाशक्तियों की निरंकुशता को दर्शा ही रहा है, यह वैश्विक कानूनों का अतिक्रमण भी है, जो अमेरिकी दादागिरी का त्रासद एवं विडम्बनापूर्ण संकेत है, वह केवल लैटिन अमेरिका तक सीमित घटना नहीं है, बल्कि समूची दुनिया के लिये एक खतरनाक मिसाल है। अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई करके वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है, उससे जुड़े कूटनीतिक, राजनीतिक और अन्तराष्ट्रीय कानून संबंधी सवाल जो खड़े हुए ही हैं, पर अमेरिका को हस्तक्षेप का अवसर देने के लिये मादुरो की नीतियां भी चर्चा में आई हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की वजहें हो सकती है, लेकिन ट्रंप को यह तो सुनिश्चित करना ही होगा कि यह राष्ट्र अस्थिरता का अड्डा न बन जाये।

अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्वयं को वैश्विक शांति का मसीहा घोषित करते नहीं थकते, लेकिन उनकी नीतियां और कार्रवाइयाँ बार-बार युद्ध, हस्तक्षेप और सत्ता परिवर्तन की मानसिकता को उजागर करती हैं। यह वही अमेरिका है जो एक ओर लोकतंत्र, मानवाधिकार और संप्रभुता की दुहाई देता है, तो दूसरी ओर एक संप्रभु राष्ट्र पर आक्रमण और उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाना अंतर्राष्ट्रीय दादागिरी का दुर्लभ उदाहरण है। उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ट्रंप ने ऐलान किया है कि सत्ता परिवर्तन होने तक वाशिंगटन इस लैटिन अमेरिकी देश का संचालन करेगा। यह एक खतरनाक परंपरा है, जिसकी पुनरावृत्ति अमेरिकी महाद्वीप से बाहर होने की आशंका भी बलवती हो सकती है। इसमें दो राय नहीं कि निकोलस मादुरो के पतन के बाद वेनेजुएला में मिश्रित प्रतिक्रिया होगी। अंतर्राष्ट्रीय साजिशों से मादुरो को लगातार खलनायक बनाने की कोशिशों में एक वैश्विक तंत्र लगा हुआ था। इस तरह की दोहरी नीतियां केवल विडंबनापूर्ण नहीं, बल्कि वैश्विक शांति के लिये घातक है। वेनेजुएला संकट को केवल मादुरो बनाम अमेरिका के टकराव के रूप में देखना वास्तविकता को सरलीकृत करना होगा। इसमें संदेह नहीं कि मादुरो सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन, दमनकारी नीतियों, चुनावी अनियमितताओं और मानवाधिकार हनन जैसे गंभीर आरोप रहे हैं। लाखों वेनेजुएलावासी देश छोड़ने को मजबूर हुए, अर्थव्यवस्था चरमरा गई और जनता त्रस्त हुई। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि किसी देश की आंतरिक विफलताओं को आधार बनाकर बाहरी सैन्य हस्तक्षेप को वैध ठहराना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आत्मा के विरुद्ध है। यदि यही मापदंड हो, तो दुनिया के अनेक देशों में बाहरी हस्तक्षेप का अंतहीन सिलसिला शुरू हो सकता है। दरअसल, वैश्विक कूटनीति के जानकारों का मानना है कि वेनेजुएला के मामले में अमेरिका की असली चिंता न लोकतंत्र है और न ही

मानवाधिकार, बल्कि वहां के विशाल तेल भंडार हैं। वेनेजुएला विश्व के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक पर बैठा देश है और ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण की अमेरिकी भूख कोई नई बात नहीं है। इराक, लीबिया और अफगानिस्तान इसके उदाहरण हैं, जहां 'लोकतंत्र स्थापना' के नाम पर हस्तक्षेप हुआ, लेकिन परिणामस्वरूप अस्थिरता, गृहयुद्ध और मानवीय संकट ही पैदा हुआ। ट्रंप का यह बयान कि मादुरो को पकड़ने के अभियान का खर्च वेनेजुएला के तेल राजस्व से वसूला जाएगा, इस पूरे घटनाक्रम की मंशा को बेनकाब करता है। यह कथन स्पष्ट करता है कि यह कार्रवाई न्याय या नैतिकता से नहीं, बल्कि संसाधनों पर नियंत्रण की साम्राज्यवादी सोच से प्रेरित है। किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों पर इस तरह दावा करना उपनिवेशवादी मानसिकता का आधुनिक संस्करण है। इस अमेरिकी कार्रवाई के भू-राजनीतिक परिणाम भी गहरे और दूरगामी होंगे। रूस और चीन ने इसे नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिये गंभीर खतरा बताया है। मादुरो के आलोचक रहे कुछ अमेरिकी सहयोगी देश भी अब खुलकर चिंता जता रहे हैं। यह संकट वैश्विक ध्रूवीकरण को और तेज कर सकता है। विशेष रूप से चीन को इस घटनाक्रम से अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं, विशेषकर ताइवान पर अमेरिकी आलोचना को कमजोर करने का अवसर मिल सकता है। यदि अमेरिका स्वयं संप्रभुता का उल्लंघन करता है, तो वह दूसरों को किस नैतिक आधार पर संयम की सलाह देगा? वेनेजुएला संकट का एक और चिंताजनक पहलू वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव है। तेल उत्पादन और आपूर्ति में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर पड़ता है। तेल कीमतों में उछाल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को झकझोर सकता है, विशेषकर विकासशील देशों को। भारत जैसे देशों के लिये यह स्थिति अत्यंत संवेदनशील है, जहां ऊर्जा आयात पर निर्भरता अधिक है। यही कारण है कि भारत ने इस घटनाक्रम पर संतुलित रुख अपनाते हुए चिंता व्यक्त की है और दोनों पक्षों से संवाद व कूटनीतिक समाधान की वकालत की है। भारत का यह दृष्टिकोण न केवल व्यावहारिक है, बल्कि नैतिक रूप से भी अधिक जिम्मेदार है। युद्ध और हस्तक्षेप किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकते। इतिहास गवाह है कि इराक और अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप के बाद अमेरिका को अंततः अपमानजनक विदाई का सामना करना पड़ा, लेकिन वे देश आज भी स्थिरता और शांति से कोसों दूर हैं। युद्ध शुरू करना भले आसान हो, लेकिन शांति और सुशासन स्थापित करना अत्यंत कठिन होता है-यह सत्य अमेरिका बार-बार भूलता रहा है। ट्रंप प्रशासन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह स्वयं को शांति का अग्रदूत बताता है, लेकिन उसकी हर बड़ी विदेश नीति पहल टकराव और दबाव की राजनीति पर आधारित दिखती है। यह दोहरी मानसिकता न केवल अमेरिका की विश्वसनीयता को कमजोर करती है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की प्रासंगिकता पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है। यदि शक्तिशाली राष्ट्र अपने हितों के अनुसार नियम तोड़ने लगें, तो वैश्विक व्यवस्था अराजकता की ओर बढ़ेगी। विरोध करे और संवाद, कूटनीति तथा बहुपक्षीय समाधान को प्राथमिकता दे। किसी भी देश में सत्ता परिवर्तन का निर्णय वहां की जनता को करना चाहिए, न कि विदेशी सेनाओं को। अंततः, अमेरिका को यह समझना होगा कि किसी 'निरंकुश शासक' को हटाना शायद सैन्य शक्ति से संभव हो जाए, लेकिन किसी देश को स्थायी शांति, स्थिरता और समृद्धि देना केवल टैंकों और बमों से नहीं हो सकता। इसके लिये धैर्य, संवेदनशीलता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान आवश्यक है। यदि अमेरिका वास्तव में वैश्विक शांति का पक्षधर है, तो उसे अपनी दोहरी नीति त्यागनी होगी। अन्यथा, वेनेजुएला जैसी घटनाएँ बार-बार दोहराई जाएंगी और दुनिया एक और अस्थिर, असुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ती जाएगी।लेखक, पत्रकार, स्तंभकार। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

सेहत की दुनिया में जरूरी सुधारों का रहा यह साल

स्वास्थ्य का मुद्दा आमतौर पर सकारात्मक कारणों से सुर्खियों में नहीं आता। साल 2025 को ही लें, तो इस क्षेत्र में सबसे बड़ी खबर कुछ राज्यों में नकली कफ सिरप से बच्चों की मौत रही है। दूसरी खबर दिल्ली में वायु प्रदूषण की रही, हालांकि साल के अंत में भारत ने पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर दूसरे विश्व सम्मेलन की मेजबानी की, जो बड़ी बात है।

(चंद्रकांत लहारिया)

इस पूरे साल देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में 'डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन' और एआई का इस्तेमाल बढ़ते देखा गया। 'ई-संजीवनी' व 'टेली-मेंटल हेल्थ सर्विसेज' जैसे डिजिटल मंचों को ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों में प्रसारित करने की कोशिश की गई। इसी तरह, मलेरिया में तेजी से कमी आई है। 2017 से 2023 के बीच इस बीमारी में 69 प्रतिशत और मृत्यु में 68 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। तमाम शोध व आंकड़े बताते हैं कि टीबी जैसी संक्रामक बीमारियों में कमी तो आई, पर डायबिटीज, हृदय रोग, मोटापा व कैंसर जैसे असंक्रामक रोग तेजी से बढ़े हैं। यह बताता है कि पारंपरिक संक्रामक रोगों पर नियंत्रण से ज्यादा जरूरी, रोकथाम और स्थायी देखभाल करना है।

इस साल कुछ बड़े सुधार हुए हैं। जैसे, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम से जीएसटी हटने से लाखों परिवारों को सहूलियत हुई और बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य बीमा हुए। मानसिक स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा को पहचान मिली। विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिये आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) पद्धतियों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलना पारंपरिक दवाओं को व्यापक बनाने के भारतीय प्रयास का नतीजा है।

हालांकि, कई काम अब भी शेष हैं। जैसे, अस्पतालों को अब 'पोस्ट-हॉस्पिटल' केयर और घर पर ही इलाज की सुविधा पर ध्यान देना चाहिए, ताकि डायबिटीज या हाई बीपी जैसी बीमारियों के मरीजों को अस्पताल नहीं जाना पड़े। वैसे, लोगों को भी घरेलू स्तर पर कुछ आदतें बना लेनी चाहिए। जैसे- वे अस्वास्थ्यकर, वसा, नमक व चीनी युक्त भोजन कम करें। नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। बचाव के उपाय इस कदर किए जाएं कि नए साल में हम अंतिम उपाय के तौर पर ही अस्पताल का रुख करें। जिस तरह से देश में असंक्रामक बीमारियों की बारंबारता बढ़ रही है, हमारी पहली रणनीति रोकथाम की होनी चाहिए। हाई बीपी, डायबिटीज, कैंसर और मोटापे को रोकने के लिए उसकी जांच-पड़ताल, जीवन-शैली में सुधार और बड़े स्तर पर टीकाकरण को आवश्यक बनाने की जरूरत है। इनमें सर्वाइकल कैंसर के लिए एचपीवी और वृद्धावस्था में लगाए जाने वाले टीके भी शामिल हैं। चयापचय

(मेटाबोलिज्म) संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए जीवन-शैली में बदलाव व सार्वजनिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। इसके लिए थाईलैंड के 'प्रिवेंटिव हेल्थ हॉस्पिटल' से सबक लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से कैंसर की रोकथाम की असम की पहल को बड़े पैमाने पर अपनाने की जरूरत है।

दवाओं के मामले में 2025 में बहुत विकास हुआ है। उदाहरण के लिए, 2025 में एक नई दवा 'लेनाकापाविर' टीका आया, जो साल में दो बार लगाने से एचआईवी संक्रमण को रोका जा सकता है। इसे जून में अमेरिकी नियामक संस्था ने मंजूरी दी थी और जुलाई में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मान्यता दे दी। कंपनी ने इसे जेनेरिक बना देने की हामी भर दी है। भारत इससे लाभ उठाकर दुनिया के लिए सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध करवा सकता है। इसी तरह, अपने यहां टीबी एक बड़ी चुनौती है। इस मोर्चे पर अच्छी खबर यह है कि चार टीकों का परीक्षण आखिरी चरण में है। टीबी में 'सोरफेक्लिलाइन' नामक नई एंटीबायोटिक ने भी उम्मीद जगाई है और यह भारत में टीबी से लड़ने के लिए 'गेम चेंजर' साबित हो सकती है। हालांकि, बेवजह दवा सेवन से परहेज किया जाना चाहिए। इस बारे में सार्वजनिक शिक्षण जरूरी है।

अगले साल सबसे जरूरी कदम होगा, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति व ज्ञान का इस्तेमाल बढ़ाना। स्वास्थ्य पर बचपन से ही ध्यान दिया जाए। स्कूल न केवल शिक्षा, बल्कि पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जरूरी जागरूकता फैलाने के भी संस्थान बनें। उम्मीद है, वर्ष 2026 स्वास्थ्य के मामले में अधिक यादगार साबित होगा।

(लेखक वरिष्ठ चिकित्सक और महामारी विशेषज्ञ है)। (ये लेखक के अपने विचार हैं)

वर्ग पहेली 5967

1	2	3	■	4	5	6	■
7			■	8			9
	■	■	10		■		
11	12			■	13	14	
15		■	■	16			■
17		18	■		■	19	
	■		■	20	21		■
22			■	23		■	24

संकेतः बाएं से दाएं
1. विश्व का सबसे बड़ा बैंक इस देश में स्थित है (3)
4. यह घोंसला न बनाने वाली पक्षी है, कोकिल (3)
7. जो रिश्तें में पति की बहन हो (3)
8. जिसकी सभी सतह समान हो, हमवार (4)
11. खैर-आफियत का अपभ्रंश, कुशल-मंगल (4)
13. मुर्गे की जाति का एक पक्षी जिसे लड़ाने के लोग पालते है (3)
15. सूजी, कण (2)
16. समाचार, खबर, संदेश (3)
17. कोई घटना अथवा कौतुक देखने के लिए एकत्रित जनसमूह, भीड़, जमघट (3)
19. काव्य की रचना करने वाला, शायर (2)
20. न्यौछावर करना, उत्सर्ग करना (3)
22. अपवित्र, अशुद्ध, अशुचि (3)
23. हजरत मुहम्मद की छंदोबद्ध स्तुति (2)
24. प्रातःकाल का अर्ध प्रकाश, प्रकाश की किरण (1)

ऊपर से नीचे
1. प्राण की रक्षा होना, कुशल मनाना (8)
2. कत्था, चूना आदि लगाकर खाया जाने वाला एक प्रसिद्ध लता का पत्ता, ताम्बूल (2)
3. नदी का पुल्लिंग (2)
4. दूरी नापने की एक प्राचीन इकाई जो लगभग दो मील के बराबर होती है (2)
5. यह कार्तिक शुक्ल द्वितीय को होने वाला पर्व भाईदूज को यह भी कहा जाता है (5)
6. दुर्व्यसन, बुरी आदत, कुटेव (2)
9. चित्रकला में लता की आकृति का अंकन (3)
10. पुत्र, बेटा (2)
12. रस्म, प्रथा, रीति (3)
14. क्रोध या आवेश में आना, तमतमाना (4)
16. शलभ (2)
18. प्रेमपात्र, प्रियतम (3)
21. मनोयोग से कार्य में लगा हुआ (2)

वर्ग पहेली 5966 का हल

र	वी	न्द्र	ना	थ	टै	गो	र
ज	र	■	या	र	■	द	म
त	■	रा	ब	■	न	भ	■
प	र	ख	■	आ	ग	रा	■
ट	का	■	आ	यु	■	ई	श
■	बी	घा	■	वँ	■	■	क
ख	■	म	द	र	गा	र	■
र	क्षा	■	शा	■	ना	द	■

आइए, इस नए वर्ष में 26 संकल्प साथ लें

(सुंदरचंद ठाकुर)

नया वर्ष आते ही हम सब कुछ नया करने की इच्छा से भर जाते हैं। नई तारीखें, नई योजनाएं और नई उम्मीदें मन में जन्म लेती हैं। लेकिन कुछ ही सप्ताह बाद वही पुरानी थकान, वही बिखरी दिनचर्या और वही अधूरे वादे लौट आते हैं। शायद इसलिए कि हम संकल्प तो लेते हैं, पर जीवन की दिशा नहीं बदलते। इस बार मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ संकल्प लें, अकेले नहीं बल्कि साथ चलकर।

1. हम यह संकल्प लें कि अपने शरीर को बोझ नहीं, साधन मानेंगे और उसे नियमित गति देंगे।
2. हम भोजन को केवल स्वाद नहीं, ऊर्जा और संतुलन के रूप में देखेंगे।
3. हम अपने मन को यह अधिकार नहीं देंगे कि हर विचार को अंतिम सत्य बना दे।
4. हम यह अभ्यास करेंगे कि विचार आएं और जाएं, पर हम उनमें उलझें नहीं।
5. हम भावनाओं को दबाएंगे नहीं, पर उन्हें अपनी पहचान भी नहीं बनाएंगे।
6. हम साक्षी भाव में रहना सीखेंगे, देखने वाले बनेंगे, डूबने वाले नहीं।
7. हम यह स्मरण रखेंगे कि हम केवल शरीर और नाम नहीं हैं, हम चेतना हैं।
8. हम हर दिन कुछ पल मौन में बैठकर केवल होने का अनुभव करेंगे।
9. हम अपने जीवन को बिना उद्देश्य के नहीं चलने देंगे।
10. हम यह प्रश्न पूछते रहेंगे कि हमारा जीवन किसके लिए है।
11. हम आलस्य नहीं, प्रेरित कर्म चुनेंगे।
12. हम यह समझेंगे कि कर्म से ही ऊर्जा पैदा होती है।
13. हम हर दिन कुछ ऐसा करेंगे जिससे भीतर जीवंतता बनी रहे।
14. हम कम अपेक्षा करेंगे और अधिक देने का अभ्यास करेंगे।
15. हम समय, ध्यान और करुणा बिना हिसाब लगाए बांटेंगे।
16. हम रिश्तों में बोलने से पहले सुनना सीखेंगे।
17. हम दूसरों को बदलने से पहले खुद को समझने का प्रयास करेंगे।
18. हम समय को खर्च नहीं, निवेश मानेंगे।
19. हम अनावश्यक भागदौड़ और व्यर्थ चिंताओं को कम करेंगे।
20. हम तुलना की आदत से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे।
21. हम यह स्वीकार करेंगे कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है।
22. हम सीखते रहेंगे, चाहे उम्र कोई भी हो।
23. हम जो है उसके लिए कृतज्ञ रहना सीखेंगे।
24. हम अपने डर को छिपाएंगे नहीं, बल्कि उसे पहचानेंगे।
25. हम जीवन को अनावश्यक रूप से जटिल नहीं बनाएंगे और सरलता को चुनेंगे।
26. अंत में, हम यह संकल्प लेंगे कि जीवन को ऑटोमेटिक नहीं जिएंगे, बल्कि हर दिन थोड़ा और जागरूक होकर जिएंगे। यदि हम इन 26 संकल्पों को निभा पाए।

ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं।

आज का राशिफल

मेष
आज कार्यक्षेत्र में अचानक कुछ बदलाव सामने आ सकते हैं। हालांकि, इससे आप घबराने वाले नहीं हैं। कानूनी या नियमों से जुड़ी उलझन को लेकर आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। ऐसे में जल्दबाजी न करें और धैर्य पूर्वक इसका समाधान निकालने की कोशिश में लग जाएं।

वृष
आज दूसरों के भरोसे लाभ कमाने की सोच से आपको बाहर निकलना होगा। कभी-कभार ये तरीका चल सकता है, लेकिन हमेशा कारगर नहीं रहेगा। लंबे समय तक आर्थिक लाभ के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। कार्यक्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की जरूरत है।

मिथुन
दिन आज ठीक-ठाक ही गुजरता दिख रहा है। दिन के पहले हिस्से में आपको कुछ उपलब्धियां मिल सकती हैं। नौकरी या व्यवसाय में चल रही परेशानियां भी धीरे-धीरे खत्म होती दिखने लगेंगी। आज आपको यह समझ आएगा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता।

कर्क
आज के दिन समाज सेवा से जुड़े लोगों के लिए अनुकूल रहने वाला है। किसी संस्था या संगठन से जुड़े हैं तो आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। आपकी पहचान और मान- सम्मान बढ़ाने वाले कई मौके आपको मिलते दिखेंगे।

सिंह
आज आपको मेहनत का फल मिलना शुरू होगा। आज आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। कार्यक्षेत्र में उदार रवैया अपनाएं और अपने से छोटे कर्मचारियों की गलतियों को नजरअंदाज करें।

कन्या
आज के दिन कन्या राशि के लोगों को संभलकर रहना होगा। दूसरों की जरूरतों को अपने काम से ऊपर रखने से नुकसान हो सकता है। अपना महत्वपूर्ण

तुला
आज कार्यक्षेत्र में दूसरों पर निर्भर रहना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अपनी शर्तों पर काम करना आपके लिए इस समय बेहद जरूरी रहेगा। सही समय पर लिया गया आपका फैसला आपके लिए फायदे का सौदा रहेगा। आत्मविश्वास के साथ उठाया गया छोटा कदम भी बड़ी लाभ दे सकता है।

धनु
आज काफी समय बाद कोई सुखद समाचार मिलने की संभावना है। कोई जरूरी काम पूरा होने से भविष्य में लाभ के अवसर मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में सकारात्मक माहौल बना रहेगा। वही, शाम तक कहीं अटका हुआ धन वापस मिलने के योग बनते दिख रहे हैं। आर्थिक दबाव कम होने से आपको राहत मिलेगी।

कुंभ
आज के दिन खुद पर भरोसा बनाए रखना होगा। धैर्य ही आज आपकी असली ताकत हैं। किसी काम के अंत में अगर हौसला छोड़ देंगे तो मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाएगा। थोड़ी सी कोशिश आपको वहां तक ले जाएगी जहां आप लंबे समय से पहुंचना चाह रहे थे।

वृश्चिक
आज कुछ भावनात्मक मुद्दे आपके सामने आ सकते हैं। आपकी करुणा और उदारता कभी-कभी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। बेहतर होगा कि नियम या कानूनी से जुड़े मामलों को सोच-समझकर कर हल करने का प्रयास करें।

मकर
आज कुछ उलझनों में घिरे रह सकते हैं। निजी जीवन और कार्यक्षेत्र में काम का दबाव बढ़ा रहेगा। आज के दिन वाहन से जुड़ी कोई समस्या भी परेशानी खड़ी कर सकती है। ऐसे में बेहतर होगा कि घबराने की बजाय शांत मन से काम लें।

मीन
आज आप आध्यात्मिक विचारों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इसका असर आपके व्यवहार में भी दिखाई देगा। कार्यक्षेत्र में कोई रुकावट आने पर शांत रहकर स्थिति को समझने की कोशिश करें। मानसिक संतुलन बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा।

1 करोड़ का पैकेज ठुकराया, जुनून ऐसा कि 3 दिन तक नहीं सोए

किसान के इस बेटे ने कैसे किया नाम

नई दिल्ली, एजेंसी।
एक किसान के बेटे के लिए 1 करोड़ रुपये सालाना की विदेशी नौकरी ठुकराना कोई आसान फैसला नहीं होता। लेकिन, हैदराबाद के एम. वेंकट नरसिम्हा रेड्डी के इरादे कुछ और ही थे। 14 साल तक फॉक्सवैगन और टेक महिंद्रा जैसी दिग्गज कंपनियों में काम करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि भारत में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर ऑटोमोटिव तकनीक विदेश से आयात की जाती है। इसी कमी को दूर करने और भारत को डीप-टेक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने अपनी जमापूंजी लगाकर नार्गा इंजीनियरिंग की शुरुआत की। यह स्टार्टअप केवल गैजेट्स नहीं बना रहा, बल्कि 5त्न टेलीमैटिक्स, ईवी चार्जिंग और भविष्य के पैसेंजर ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकों पर काम कर रहा है। वेंकट की यह यात्रा एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर वैश्विक स्तर की इंजीनियरिंग लैब खड़ी करने की एक मिसाल है। आइए, यहां एम. वेंकट नरसिम्हा रेड्डी की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं।

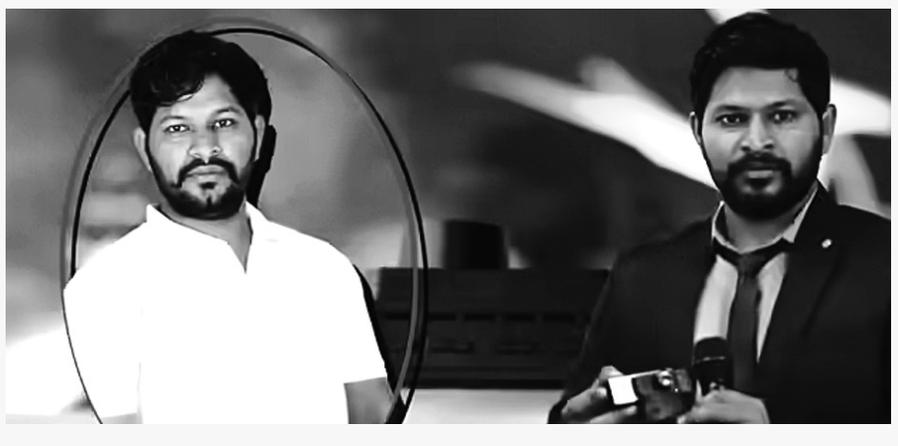

आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव अकावेदु के किसान परिवार में जन्मे वेंकट का सफर संघर्षों से भरा रहा। उनके पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए 16 एकड़ जमीन बेच दी थी। इसका कर्ज वेंकट ने अपनी मेहनत और काबिलियत से चुकाया। दुनिया की टॉप ऑटोमोटिव कंपनियों में 14 साल काम करने के दौरान उन्होंने देखा कि भारत उच्च स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पूरी तरह विदेश पर निर्भर है। इसी निर्भरता को खत्म करने के लिए उन्होंने साल 2024 में नार्गा इंजीनियरिंग की नींव रखी। उनका विजन सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि भारत को इंजीनियरिंग पावरहाउस बनाना है। नार्गा इंजीनियरिंग का सबसे अहम प्रोडक्ट 5जी नेटिव टेलीमैटिक्स कंट्रोल यूनिट है, जिस पर वेंकट पिछले 3 सालों से रिसर्च कर रहे थे। कंपनी ने सेसला नाम से एक कंज्यूमर ब्रांड भी लॉन्च किया है। इसके तहत एडवांस्ड डैशबोर्ड कैमरे बाजार में उतारे गए हैं। ये कैमरे न केवल सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि भारतीय सड़कों की खास जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। इसके अलावा, कंपनी 5जी और भविष्य की 6जी-7जी तकनीक पर आधारित सिस्टम-ऑन-चिप विकसित करने पर भी काम कर रही है।

2030 तक इस टारगेट पर नजर

वेंकट का मानना है कि असली विकास तभी होगा जब भारत के इंजीनियरिंग छात्र असली हार्डवेयर पर काम करेंगे। इसके लिए उन्होंने 3,000 से 5,000 की किफायती आरएंडडी किट तैयार की है। लेकिन, नार्गा का विजन यहीं नहीं रुकता। कंपनी के भविष्य के रोडमैप में कृषि ड्रोन, ईवी चार्जर्स और ऐसे पैसेंजर ड्रोन शामिल हैं जो शहर के भीतर यात्रा के समय को 10 मिनट से कम कर देंगे। कंपनी का टारगेट 2030 तक 6,000 से 12,000 करोड़ रुपये की वैल्यूएशन हासिल करना है। स्टार्टअप की सबसे खास बात यह है कि वेंकट ने इसमें अपनी 13 साल की बचत के 4.5 करोड़ रुपये निवेश किए हैं। उन्होंने रात-रात भर जाकर कोडिंग की ।

रिलायंस के रूसी तेल नहीं खरीदने से कई वर्षों में सबसे कम रहेगा आयात

दावा- तीन हफ्तों से नहीं पहुंची खेप

नई दिल्ली, एजेंसी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के रूस से कच्चे तेल नहीं खरीदने से जनवरी में रूसी तेल का आयात कई वर्षों के निचले स्तर पर आ सकता है। रिलायंस ने कहा, उसे रूस से तेल की कोई भी खेप जनवरी में मिलने की उम्मीद नहीं है। रिलायंस का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रविवार को दी गई उस चेतावनी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिका भारत पर आयात शुल्क और बढ़ा सकता है। रिलायंस ने सोशल मीडिया पर कहा, पिछले तीन सप्ताह से रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी में रूसी तेल की कोई खेप नहीं पहुंची है। दरअसल, 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत रियायती दरों पर मिलने वाले रूसी समुद्री कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा। तब से अब तक भारत ने रूस से 144 अरब यूरो मूल्य का कच्चा तेल खरीदा है। इस दौरान चीन रूस से 210.3 अरब यूरो का क्रूड आयात कर सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। भारत दूसरे स्थान पर है। इन खरीदों ने पश्चिमी देशों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया को जन्म दिया है, जिन्होंने रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाकर उसे निशाना बनाया है। उनका तर्क है कि तेल राजस्व से मॉस्को के युद्ध प्रयासों को वित्त पोषित करने में मदद मिलती है। अमेरिका ने पिछले साल रूसी तेल की भारी खरीद के लिए दंड के रूप में भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क दोगुना करके 50 फीसदी कर दिया था। 20 नवंबर, 2025 को रिलायंस ने कहा था कि उसने यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का अनुपालन करने के लिए गुजरात के जामनगर स्थित अपनी निर्यात आधारित रिफाइनरी में रूसी कच्चे तेल का उपयोग बंद कर दिया है। रिलायंस भारत में रूस से तेल खरीदने वाली सबसे बड़ी कंपनी थी। वह जामनगर के अपने तेल शोधन परिसर में कच्चे तेल को रिफाइंड करके पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों में परिवर्तित करती थी। इस परिसर में दो रिफाइनरियां हैं। कंपनी ने मंगलवार को उस रिपोर्ट को पूरी तरह से असत्य बताया जिसमें दावा किया गया था कि रूसी तेल से लदे तीन जहाज रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी के लिए तैयार किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि लगभग 22 लाख बैरल यूराल (रूसी कच्चे तेल का एक ग्रेड) से लदे कम से कम तीन टैंकर सिक्का बंदरगाह की ओर जा रहे थे। इसके माध्यम से जामनगर रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स अपने कच्चे तेल के आयात का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है।

माचिस से भी कम कीमत का शेयर

ऐसा क्या हुआ कि लुढ़कते बाजार में चढ़ने लगा

मुंबई, एजेंसी।
एग्री टेक्नोलॉजी और कुछ एग्रीकल्चर जीन्सों का निर्यात करने वाली इंदौर की एक कंपनी है एग्री ग्रो लिमिटेड । नेलशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड इस कंपनी ने पिछले दिनों खबर दी कि इसने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस इनेबल्ड एक कार्बन क्रेडिट प्लेटफॉर्म कार्बन कृषि लॉन्च किया है। इसके बाद इसके शेयर भागने लगे। इससे पहले इसके शेयर लगातार नौ सेशन में लुढ़के हैं।

एनएसई के आंकड़ों को देखें तो इसके शेयर बीते 22 दिसंबर तक हर रोज चढ़ कर बंद हो रहे थे। उस दिन इसके एक शेयर का भाव 96 पैसे थे। उसके बाद यह शेयर हर रोज गोता खा रहा था। इसके शेयरों का लुढ़कना बीते दो जनवरी तक जारी रहा। तब तक यह लुढ़कते हुए 70 पैसे तक आ गया था। लेकिन पांच जनवरी को इसके शेयर अपर सर्किट में फंस कर 73 पैसे पर बंद हुए। छह फरवरी को भी इसके शेयरों में 4.17 फीसदी यानी 3 पैसे की तेजी आई और यह 75 पैसे पर बंद हुआ। इस शेयर का सर्किट पांच फीसदी का है। उल्लेखनीय है कि बीते सोमवार और मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट रही है।

बीते सोमवार यानी पांच जनवरी को कंपनी ने एनएसई को अपने रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अंकित कंसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड से कंफर्मेशन सर्टिफिकेट मिलने की सूचना दी। कंपनी ने इस सर्टिफिकेट का सबमिशन भी शेयर बाजार में किया। इसके बाद छह जनवरी को ऑरी ग्रो इंडिया लिमिटेड ने बताया कि उसने एक नया एआई-सक्षम कार्बन क्रेडिट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम कार्बनकृषि है। इसके बाद कंपनी के शेयर भागने लगे। कार्बनकृषि प्लेटफॉर्म एआई एनालिटिक्स, सैटेलाइट इमेजरी, फसल और मिट्टी के डेटा का उपयोग करके बनाया जा रहा है। बताया गया है कि यह किसानों के खेतों में कार्बन के प्रभाव का अनुमान लगाएगा। कंपनी ने कहा है कि वे करीब 1 लाख किसानों को जोड़ना चाहते हैं। ये किसान खास तौर पर खेती वाले इलाकों से होंगे।

क्या होगा इससे फायदा

ऑरी ग्रो इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर, प्रतीक कुमार पटेल के मुताबिक कार्बनकृषि के माध्यम से, हमारा उद्देश्य किसानों को जलवायु-सकारात्मक और टिकाऊ खेती के तरीके अपनाने में मदद करना है। इससे उन्हें अतिरिक्त आय मिलेगी। साथ ही, कंपनी के लिए एक स्केलेबल, एसेट-लाइट राजस्व धारा बनेगी। उन्होंने आगे कहा, एआई, डेटा एनालिटिक्स और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सत्यापन ढांचे का लाभ उठाकर, हम भारतीय कृषि को वैश्विक कार्बन क्रेडिट पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करना चाहते हैं।

बढ़ेगी आमदनी

कंपनी का अनुमान है कि इससे सालाना 16 से 50 करोड़ रुपये का कुल कार्बन क्रेडिट मूल्य मिल सकता है। हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सत्यापन कैसा होता है और वैश्विक कार्बन की कीमतें क्या रहती हैं। कंपनी को प्लेटफॉर्म की भागीदारी या कमीशन से 20 से 30 फीसदी हिस्सा मिल सकता है। इससे कार्बन क्रेडिट से कंपनी को सालाना 3 से 10 करोड़ रुपये का संभावित राजस्व मिल सकता है।

डिस्क्लेमर- इस विश्लेषण में दिए गए सुझाव व्यक्तिगत विश्लेषकों या ब्रोकिंग कंपनियों के हैं, एनबीटी के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श कर लें।

टाटा लगाएगी देश की सबसे बड़ी फैक्ट्री, चीन को मिलेगी टक्कर

इस फैक्ट्री के लिए कंपनी 6675 करोड़ रुपये निवेश करेगी

नई दिल्ली, एजेंसी।
टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में 10 गीगावाट की एक नई इनगॉट और वेफर बनाने वाली फैक्ट्री लगाएगी। यह देश की सबसे बड़ी ऐसी फैक्ट्री होगी। इस फैक्ट्री के लिए कंपनी 6675 करोड़ रुपये निवेश करेगी। इनगॉट और वेफर सेमीकंडक्टर चिप्स , सोलर सेल और मॉड्यूल बनाने के लिए बहुत जरूरी कच्चे माल हैं।

आंध्र प्रदेश सरकार ने टीपीआरईएल के लिए इफको किसान स्पेशल इकोनॉमिक जोन (में 200 एकड़ जमीन दी है। इसमें से 120 एकड़ जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होगी और बाकी 80 एकड़ भविष्य में विस्तार के लिए रखी जाएगी। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की उस नीति के तहत है जिसका मकसद सोलर उपकरण का भारत में ही उत्पादन बढ़ाना है, ताकि जरूरी पुर्जों के लिए चीन पर निर्भरता कम हो सके।

राज्य के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने कहा, आंध्र प्रदेश को टाटा ग्रुप से एक और बड़ी उपलब्धि की मेजबानी करते हुए गर्व हो रहा है। यह प्रोजेक्ट हमारे राज्य की नीतियों की स्थिरता, तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में एक मजबूत विश्वास दिखाता है। नारा लोकेश रोजगार सृजन पर बनी कैबिनेट कमेटी के प्रमुख भी हैं।

1000 लोगों को मिलेगा रोजगार

राज्य के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाले स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ने मंगलवार को इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट इस हफ्ते कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाएगा। कंपनी की तरफ से राज्य सरकार को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से करीब 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। आंध्र प्रदेश सरकार टीपीआरईएलको अपनी फैक्ट्री के लिए ग्रीन एनर्जी सप्लाई करने के लिए 200 मेगावाट का एक प्लांट लगाने के लिए भी जमीन देगी। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि ग्रीन एनर्जी की उपलब्धता इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे खास वजह थी।

कंपनियों ने एक साल में बांटे 60,800 करोड़

नई दिल्ली, एजेंसी। बीमा बाजार में एजेंटों को मिलने वाले भारी-भरकम कमिशन पर अब कैंची चल सकती है। इसे लेकर नए नियम बनाने की तैयारी चल रही है ताकि ग्राहकों को मिस-सेलिंग और महंगे प्रीमियम से बचाया जा सके। इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीएआई ने चेतावनी दी है कि डिस्ट्रीब्यूशन (पॉलिसी बेचने) का खर्च बढ़ने की वजह से इंश्योरेंस प्रीमियम महंगा हो रहा है। कंपनियों की तरफ से एजेंटों को ज्यादा पैसा देने के चक्कर में आम लोगों को महंगी पॉलिसी खरीदनी पड़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बढ़ते खर्च पर चिंता जाहिर की है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि जब पहले साल में एजेंटों को बहुत ज्यादा कमिशन मिलता है, तो मिस-सेलिंग (गलत जानकारी देकर पॉलिसी बेचना) के मामले भी बढ़ जाते हैं। ज्यादा पैसे के लालच में एजेंट ग्राहकों को गलत तरीके से पॉलिसी थमा देते हैं।

अपनी कमाई कहां इन्वेस्ट कर रहा जेन, किस पर कर रहा अधिक भरोसा

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय शेयर मार्केट में अब युवाओं ने अपनी पैठ बना ली है। 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए जेन-जी निवेशक अब बचत ही नहीं, बल्कि स्मार्ट निवेश भी कर रहे हैं। ये निवेशक तकनीक का सहारा लेकर म्यूचुअल फंड और इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं। खास बात यह है कि यह बदलाव सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों के युवा भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज के दौर में युवा निवेशक पारंपरिक एजेंटों के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक, अक्तूबर 2025 में हुए नए एसआईपी रजिस्ट्रेशन में से 8 रजिस्ट्रेशन फिनटेक ऐप्स के जरिए हुए। इसके अलावा, एसआईपी कलेक्ट करने वाले टॉप-50 संस्थानों में 14 केवल फिनटेक प्लेटफॉर्म हैं। यह दिखाता है कि निवेश अब मोबाइल ऐप के जरिए कितना आसान हो गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़े बताते हैं कि बाजार में युवाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। मार्च 2019 में 30 साल से कम उम्र के निवेशक केवल 22.6 प्रतिशत थे, जो अब बढ़कर लगभग 38 प्रतिशत हो गए हैं। फोनपे वेल्थ की रिपोर्ट भी कुछ ऐसा ही इशारा करती है। उनके म्यूचुअल फंड निवेशकों में लगभग 48 प्रतिशत लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। लगभग 95 प्रतिशत युवा निवेशक अपनी निवेश यात्रा की शुरुआत इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड से करते हैं। कोरोना महामारी के बाद बाजार में आई तेजी ने युवाओं का भरोसा बढ़ाया है। इसी वजह से वे अब इंडेक्स फंड और ईटीएफ जैसे लंबी अवधि के विकल्पों को ज्यादा चुन रहे हैं। निवेश के मामले में युवा निवेशक एसआईपी यानी हर महीने छोटी रकम जमा करने को सबसे बेहतर मानते हैं।

मुकेश अंबानी को 3,93,97,60,39,000 की चपत

गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में टॉप 20 से बाहर

नई दिल्ली, एजेंसी। देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में मंगलवार को भारी गिरावट आई। कारोबार के दौरान यह 5 फीसदी तक गिर गया था। इससे कंपनी के मार्केट कैप में करीब 1 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में 4.37 अरब डॉलर यानी करीब 3,93,97,60,39,000 रुपये की गिरावट आई। अंबानी की नेटवर्थ अब 103 अरब डॉलर रह गई है। वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 18वें नंबर पर हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ में 4.21 अरब डॉलर की गिरावट आई है। इस बीच अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में टॉप 20 से बाहर हो गए हैं। मंगलवार को उनकी नेटवर्थ में 313 मिलियन डॉलर की गिरावट आई। वह 85.4 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ 21वें नंबर पर खिसक गए हैं। अमेरिका के थॉमस पीटरफी (87 अरब डॉलर) अब उनसे आगे निकल गए हैं। एलन मस्क इस लिस्ट में पहले नंबर पर जमे हुए हैं। हालांकि मंगलवार को उनकी नेटवर्थ 13.4 अरब डॉलर गिरकर 630 अरब डॉलर रह गई। गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज 270 अरब डॉलर के साथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। ऐमजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस की नेटवर्थ में मंगलवार को 7.18 अरब डॉलर की तेजी आई। वह 262 अरब डॉलर की तेजी के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन (251 अरब) चौथे, ओरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन ((246 अरब)) पांचवें, फेसबुक के मार्क जकरबर्ग (233 अरब) छठे, बर्नार्ड आरनॉल्ट (207 अरब) सातवें, माइक्रोसॉफ्ट के स्टीव बालमर (.167 अरब) आठवें, एनवीडिया के सीईओ जेंसन हुआंग (.155 अरब) नौवें और दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे (.150 अरब) दसवें नंबर पर हैं।

मैगी बनाने वाली कंपनी के बेबी प्रोडक्ट्स पर दुनियाभर में हाहाकार, 25 देशों में वापस मंगाया सामान

नई दिल्ली, एजेंसी।
नेस्ले ने यूरोप के कई देशों में बच्चों के दूध के कुछ बैच वापस मंगाने का फैसला किया है। कंपनी ने सोमवार को अपनी वेबसाइट पर बताया कि उन्हें सप्लायर से क्वॉलिटी की समस्या मिली है। नेस्ले उन सभी वस्तुओं की जांच कर रही है, जिनका इस्तेमाल इन प्रॉडक्ट्स को बनाने में किया गया था। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर इन प्रॉडक्ट्स की तस्वीरें जारी की हैं। इनमें एसएमए, बीईबीए और एनएएन फॉर्मूला शामिल हैं।

इन उत्पादों में एक जहरीला पदार्थ मिल सकता है, जिससे उल्टी और मतली जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह रिकॉल दिसंबर में छोटे पैमाने पर शुरू हुआ था। नेस्ले किटकैट से लेकर नेस्कैफे तक बनाती है। कंपनी का कहना है कि रिकॉल किए गए उत्पादों से जुड़ी कोई भी बीमारी अभी तक कन्फर्म नहीं हुई है। ऑस्ट्रिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस रिकॉल से नेस्ले की 10 से ज्यादा फैक्ट्रियों के 800 से ज्यादा उत्पाद प्रभावित हुए हैं। उसने इसे कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉल बताया। नेस्ले के एक प्रवक्ता इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की।

नेस्ले का बाजारत्न नेस्ले के एक प्रवक्ता ने कहा कि एक बड़े सप्लायर से क्वालिटी की समस्या सामने आने के बाद नेस्ले ने सभी एराकिडोनिक एसिड ऑयल और संबंधित ऑयल मिक्स का परीक्षण किया, जिनका इस्तेमाल शिशु पोषण उत्पादों के उत्पादन में हुआ था।

MIRAE ASSET
Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAP:

Date	Time	Address
January 11, 2026	7:00 P.M.	Hotel KC, Cross Road, Sector 10, Panchkula, Haryana.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625)
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. ☎ 1800 2090 777 (Toll free), ✉ customercare@miraeasset.com 🌐 www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

किसी भी छात्र के लिए उसके करियर ऑप्शन का चयन करना एक बेहद ही महत्वपूर्ण निर्णय है। एक बार जब छात्र अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो वे अपने करियर को एक शेप देना चाहते हैं। आर्टस में बैचलर डिग्री यानी बीए एक ऐसा कोर्स है, जिसे अधिकतर बच्चे चुनते हैं।

बी.ए. करने के बाद इन करियर फील्ड में करें ट्राई

आर्टस स्ट्रीम के बच्चों के लिए बीए करना एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है। हालांकि, इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। इसमें आप इंग्लिश से लेकर पॉलिटिक्स और मनोविज्ञान तक किसी खास विषय को चुनते हैं।

अमूमन यह माना जाता है कि बीए करने के बाद करियर ऑप्शन सीमित हो जाते हैं। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। आप बीए करने के बाद कई अलग-अलग फील्ड में अपना करियर देख सकते हैं। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि बीए करने के बाद आप किन फील्ड में करियर बना सकते हैं-

जर्नलिज्म में आजमाएं हाथ

बीए करने के बाद एडवरटाइजिंग या जर्नलिज्म की फील्ड में करियर के अवसर देखे जा सकते हैं। आप बीए करने के बाद जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन से जुड़ा कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद आप टीवी से लेकर रेडियो, अखबार व ऑनलाइन वेबसाइट्स आदि के लिए काम कर सकते हैं। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म, पॉडकास्ट, ब्लॉग और एड आदि सभी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं।

सिविल सर्विसेज की करें तैयारी

अगर आप चाहें तो बीए करने के बाद सिविल सर्विसेज एग्जाम जैसे यूपीएससी आदि की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा, स्टेट लेवल एग्जाम का हिस्सा बनें।

अगर आप इसे क्लीयर कर पाते हैं तो आपको बिना किसी परेशानी के आसानी से गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है और गवर्नमेंट सर्विसेज का हिस्सा बन जाते हैं।

करें प्रोफेशनल राइटिंग

बीए करने के बाद आप प्रोफेशनल राइटिंग के क्षेत्र में भी हाथ आजमा सकते हैं। आमतौर पर, यह एक क्रिएटिव फील्ड है, जिसमें आप अपने विचारों को बेहद ही खास तरह से पेश करते हैं। यदि आपके पास साहित्य में डिग्री है, तो आप निश्चित रूप से क्रिएटिव राइटिंग की फील्ड में काम कर सकते हैं। आप स्क्रिप्ट, से लेकर भाषण, स्क्रीनप्ले, कविताएं आदि लिख सकते हैं। अगर आपका लेखन अच्छा है तो आप प्रोफेशनल राइटिंग करके अच्छी खासी कमाई कर सकती है।

करें लॉ

अगर आप बीए की डिग्री हासिल करने के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, तो आप बैचलर ऑफ लॉ या एलएलबी चुन सकते हैं। इस तीन साल के कोर्स के बाद आपको लीगल रीजनिंग से लेकर एनवायरनमेंटल लॉ, इंश्योरेंस लॉ आदि की गहन जानकारी हो जाती है। आप चाहें तो इसके बाद एलएलएम भी कर सकते हैं।

करें बिजनेस मैनेजमेंट

बीए करने के बाद आप बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर सकते हैं। यह एक साल का शॉर्ट टर्म कोर्स है, जिसमें छात्रों को अलग-अलग बिजनेस एक्टिविटीज और मैनेजमेंट से जुड़े सिद्धांतों का ज्ञान मिलता है। इसके बाद आप कई अलग-अलग आर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर सकते हैं या फिर खुद का बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं।

बॉस से छुट्टी मांगते वक्त इन बातों का रखें खास ध्यान

बॉस से छुट्टी मांगना आमतौर पर आसान नहीं होता है। कई बार प्लान बनाने से पहले ही सोचना होता है कि छुट्टी कैसे मिलेगी। हालांकि, कई बार छुट्टी लेने के कुछ और तरीकों को भी अपनाकर आप अपने बॉस से लंबी छुट्टी ले सकते हैं। आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि जब आप अपने बॉस से छुट्टी मांगने जाते हैं तो आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए।

प्री प्लान करें

छुट्टी के लिए अचानक से बोलने पर हो सकता है कि आपको छुट्टी नहीं मिले। अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आपको अपने बॉस से पहले से बात कर लेना चाहिए। ऐसे में आपको आसानी से छुट्टी मिल सकती है। इसके अलावा, आपकी गैर-मौजूदगी में आपका काम कौन संभालने वाला है, इसके बारे में भी आपको अपने बॉस से बात कर लेना चाहिए।

बैकअप प्लान करें

लंबी छुट्टी अप्लाई करते समय आपको बैकअप का प्लान तैयार कर लेना चाहिए, ताकि आपकी गैर-मौजूदगी में किसी भी तरह की दिक्कत आती है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना हो। बैकअप बनाने के बाद अगर आप छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको आसानी से छुट्टी मिल जाएगी।

छुट्टी का कारण

अगर आपको अचानक छुट्टी चाहिए, तो सॉलिड कारण लेकर ही बॉस के पास छुट्टी मांगने जाना चाहिए। अगर आप यह बोलेंगे कि आपको घूमने जाना है, तो हो सकता है कि आपको छुट्टी न मिल पाए। ऐसे में आपको पहले से कारण तैयार रखना होगा कि आपको अपने बॉस से क्या कहना है।

बॉस का मूड देखकर बात करें

आपको छुट्टी मांगने से पहले अपने बॉस का मूड देख लेना चाहिए। अगर आपके बॉस का मूड अच्छा है, तो आपको तुरंत छुट्टी मिल सकती है। बॉस का मूड खराब होने पर आपको छुट्टी मिलने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में मूड के हिसाब से ही आपको बात करना चाहिए।

अनेक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करती है साइंस की फील्ड

साइंस के क्षेत्र में अच्छे कोर्स करने के बाद, छात्र मालामाल हो सकते हैं, जो उन्हें अनेक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। यहां कुछ कोर्स हैं जो छात्रों को साइंस क्षेत्र में सफलता की ओर ले जा सकते हैं। इन कोर्स के साथ-साथ, छात्रों को निरंतर अध्ययन करने का प्रैक्टिकल अनुभव भी मिल सकता है।

स्पेस टेक्नोलॉजी

स्पेस टेक्नोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा है, जिसके अंतर्गत कॉस्मोलॉजी, स्टारर साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स, प्लेनेटरी साइंस, एस्ट्रोनॉमी आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। इस विषय में डिग्री हासिल करने के बाद आप स्पेस साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, मैटीरियोलॉजिस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट, रडार टेक्नीशियन, सेटेलाइट टेक्नीशियन आदि के रूप में नासा, इसरो एवं डीआरडीओ जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए योग्यता फिजिक्स, केमिस्ट्री व मैथमेटिक्स के साथ बारहवीं होनी चाहिए। ये प्रोग्राम पास करने के बाद आप स्पेस साइंस के बैचलर प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। इसके लिए आपको ऑल इंडिया लेवल पर आयोजित प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी। स्नातक के बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं। आप अगर इस क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पीएचडी करना होगा।

कहां से करें कोर्स

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी
- तिरुवनंतपुरम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भुवनेश्वर।
- आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जरवेशनल साइंसेज,
- नैनीताल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बेंगलुरु।

फूड टेक्नोलॉजी

अच्छे खानपान का शौक रखने के साथ फूड प्रोडक्ट में प्रयोग होने वाले रसायनों, खाद्य पदार्थों के रखरखाव, उन्हें पैक करने के तरीकों एवं मार्केटिंग से संबंधित बातों में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए फूड साइंस एवं टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में एक बेहतरीन करियर ऑप्शन बन कर उभरा है। एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में छात्र फूड प्रोसेसिंग कंपनियों, फूड रिसर्च लेबोरेटरी, होटल, रेस्टोरेंटों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में करियर की संभावनाएं तलाश सकते हैं।

योग्यता क्या होगी?

इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स या होम साइंस के साथ 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके बाद आप फूड साइंस, केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी में बैचलर डिग्री कर सकते हैं। बैचलर डिग्री करने के बाद फूड केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और अन्य क्षेत्रों में एडवांस डिग्री भी कर सकते हैं। आप चाहें तो डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन और फूड साइंस एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में डिप्लोमा कर सकते हैं। स्नातक के बाद परास्नातक व रिसर्च करने का विकल्प भी है।

कहां से करें कोर्स

- सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी
- नेशनल एग्री फूड बायो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट
- राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कोटा
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन
- नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट अन्ना यूनिवर्सिटी

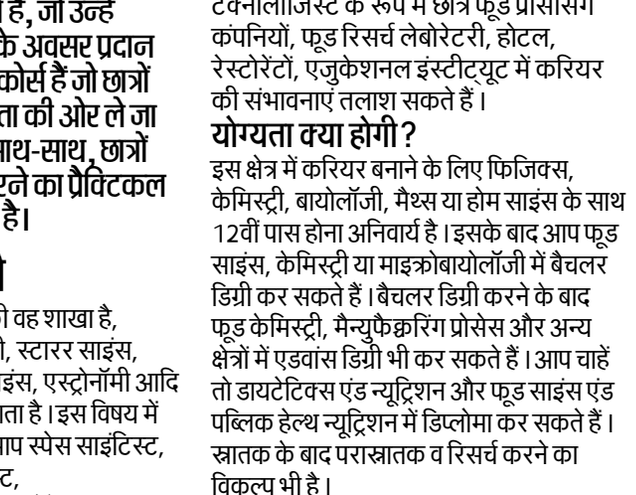

मरीन इंजीनियरिंग

मरीन इंजीनियरिंग असल में इंजीनियरिंग की एक शाखा है, जिसमें जहाजों, नावों, पनडुब्बियों और अन्य जलयानों को डिजाइन किया जाता है। मरीन इंजीनियर समुद्री जहाज के सफलतापूर्वक संचालन में अहम भूमिका निभाते हैं और समुद्र एवं उसके आसपास उपयोग की जाने वाली मशीनों का डिजाइन, रखरखाव, निर्माण करते हैं। इस विषय में डिग्री हासिल करने के बाद आप गवर्नमेंट एवं प्राइवेट शिपिंग कंपनियों, से क्राफ्ट डिजाइनिंग एवं बिल्डिंग, इंजन प्रोडक्शन फर्म में आकर्षक जॉब हासिल कर सकते हैं। मरीन इंजीनियर के लिए भारत और विदेश में भी करियर के अवसरों की एक विस्तृत गुंजाइश है। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी विभाग में जॉब कर सकते हैं।

योग्यता क्या होगी?

- साइंस बैकग्राउंड के छात्र मरीन इंजीनियरिंग या ओशेन इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक कोर्स के साथ इस करियर में दाखिल हो सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद इस विषय में मास्टर्स कर सकते हैं।

कहां से करें कोर्स

- इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, कोलकाता
- आईआईटी मद्रास
- बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस मरीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराते हैं।

फॉरेंसिक साइंस

फॉरेंसिक साइंस आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। फॉरेंसिक साइंटिस्ट किसी घटना से जुड़े छोटे-छोटे सुराग के जरिये मुजरिम तक पहुंचने और उनसे संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं को समझने के काम करते हैं। आप अगर साइंस बैकग्राउंड के छात्र हैं और जुर्म करने वाले को किसी भी हाल में सामने लाने का जुनून रखते हैं, तो फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में जॉब के मौके उपलब्ध हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आप इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी), सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई), स्टेट पुलिस फोर्स के क्राइम सेल, गवर्नमेंट व स्टेट फॉरेंसिक लैब में काम कर सकते हैं। वहीं, प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी में फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप चाहें तो फॉरेंसिक टीचर के रूप में भी करियर बना सकते हैं।

योग्यता क्या होगी?

साइंस स्ट्रीम से बारहवीं पास करने के बाद आप फॉरेंसिक साइंस में स्नातक कर सकते हैं। स्नातक के बाद फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनोलॉजी में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, मास्टर करने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायो केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बी फार्मा, बीडीएस और एप्लाइड साइंस में से किसी एक विषय के साथ न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से स्नातक पास करना होगा। अगर आप फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको एमबीबीएस डिग्री प्राप्त करनी होगी और इसके बाद फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में एमडी भी करना होगा।

कहां से करें कोर्स

- लोक नायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, दिल्ली
- सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, हैदराबाद
- सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, चंडीगढ़
- डॉ भीमराव आंबेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा
- गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली
- इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी
- बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी

इन संस्थानों से आप बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस, डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी, डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस एंड लॉ, एमएससी इन क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, एमएससी इन साइबर फॉरेंसिक्स एंड इनफॉर्मेशन सिक्योरिटी आदि कोर्स कर सकते हैं।

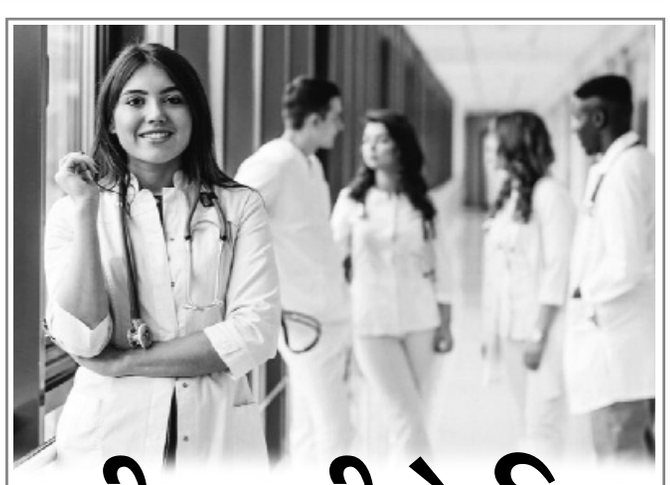

नीट यूजी के लिए ऐसे करें अप्लाई

भारत में मेडिकल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, उम्मीदवारों को नीट के लिए परीक्षा दिशानिर्देशों का पालन करना होता है, जो कई कैटेगरी से आने वाले छात्रों के लिए अलग-अलग होती हैं। नीट में शामिल होने के लिए, उम्मीदवारों को एनटीए के तरफ से तय की गई नीट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरी करनी होगी। चूंकि, इस बार एनटीए ने नीट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल दी है, इसमें बिना जीव विज्ञान विषय पढ़े छात्र भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आयोग ने नीट में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए चिकित्सा क्षेत्र के में विस्तार करने का अहम फैसला लिया है। अब, अलग से विषय के तौर पर जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी पढ़ने वाले उम्मीदवार भी नीट की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इस तरह ऐसे छात्र डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं।

नीट यूजी के लिए स्टेप-बाय-स्टेप ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

- सबसे पहले, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ऑफिसियल वेबसाइट https://neet.nta.nic.in/ पर जाएं।
- अब, वेबसाइट पर "New Registration" के लिंक को सर्च करके क्लिक करें। अपनी पर्सनल जानकारी, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करें। कोशिश करें कि स्ट्रांग पासवर्ड बनाएं और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी कर लें।
- फिर अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन करें।
- इसके बाद "Fill Application Form" के सेक्शन में जाएं और सभी जानकारी सावधानी से भरें। आपको अपनी निजी जानकारी, एकेडमिक एलिजिबिलिटी, एग्जाम सेंटर से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। यह ध्यान रखें कि सभी जानकारी सही और सटीक हैं।
- डॉक्यूमेंट अपलोड करें, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10 वीं और 12 वीं की मार्कशीट आदि। अपलोड किए गए डॉक्युमेंट के साइज और फॉर्मेट वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों के मुताबिक होनी चाहिए।
- एप्लीकेशन फीस का ऑनलाइन पेमेंट करें। पेमेंट के लिए आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- पूरी जानकारी भरने और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर लें। फॉर्म में सारी जानकारी सही होने पर "Final Submit" बटन पर क्लिक करें।

जरूरी बातें

- अप्लिकेशन फॉर्म भरते समय सावधानी बरतें और किसी भी गलती से बचें, वरना अप्लिकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है।
- एप्लीकेशन फीस का पेमेंट समय से पहले ही कर लें।
- सभी जरूरत के डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
- एप्लीकेशन जमा करने से पहले उसकी प्रूफरीडिंग कर लें।
- अधिक जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क करें।

इन टिप्स को करें फॉलो

- परीक्षा की तैयारी के लिए NCERT की किताबों को पढ़ें।
- पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करें।
- पेपर से पहले ऑनलाइन मॉक टेस्ट दें।

कौन हैं रिद्धिमा पाठक?

...जिन्होंने बांग्लादेशी लीग को मारी ठोकर, बोलीं- मेरे लिए देश पहले

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर रिद्धिमा पाठक ने यह पुष्टि की है कि उन्होंने खुद बांग्लादेश प्रीमियर लीग के ब्रॉडकास्टिंग पैनल से हटने का फैसला लिया था और उन खबरों को खारिज किया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि उन्हें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हटा दिया है. उनका यह स्पष्टीकरण ऐसे समय पर आया है, जब भारतीय और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड्स के बीच तनाव चरम पर है.

BPL से बाहर होने को लेकर चल रही अटकलों के बीच रिद्धिमा पाठक ने सीधे तौर पर इन दावों पर प्रतिक्रिया दी और अपने हटने की वजह स्पष्ट की. उनका यह फैसला ऐसे दौर में सामने आया है, जब दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंधों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और मीडिया व फैंस हर घटनाक्रम को करीब से फॉलो कर रहे हैं.

क्या बोलीं रिद्धिमा पाठक

अपने सार्वजनिक बयान में रिद्धिमा पाठक ने कहा, 'पिछले कुछ घंटों में एक कहानी चलाई जा रही है कि मुझे BPL से 'ड्रॉप' कर दिया गया. यह सच नहीं है. मैंने खुद निजी तौर पर बाहर होने का फैसला लिया. मेरे लिए मेरा देश हमेशा पहले आता है. और मैं क्रिकेट को किसी एक असाइनमेंट से कहीं ऊपर मानती हूं. मुझे सालों से इस खेल की ईमानदारी, सम्मान और जुनून के साथ सेवा करने का सौभाग्य मिला है. यह कभी नहीं बदलेगा. मैं आगे भी ईमानदारी, स्पष्टता और खेल की भावना के साथ खड़ी रहूंगी.'

जाने रिद्धिमा को

रिद्धिमा का जन्म 17 फरवरी साल 1990 में झारखंड की राजधानी रांची में हुआ था. पेशे से वह

मॉडल, एक्टर, वॉइस आर्टिस्ट, टीवी प्रजेंटर और एंकर हैं. रिद्धिमा ने अपने करियर की शुरुआत एक रेडियो स्टेशन में इंटर्नशिप के जरिए की थी. वह स्टार स्पोर्ट्स, टेन स्पोर्ट्स, सोनी और जियो पर काफी सारे स्पोर्ट्स ईवेंट्स को प्रजेंट कर चुकी हैं. रिद्धिमा को खास पहचान टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान मिली.रिद्धिमा ने कई बड़े स्टार क्रिकेटर्स का इंटरव्यू किया है.

यूनाईटेड कप

कोको गॉफ की दमदार जीत

पर्थ, एजेंसी। अमेरिकी स्टार टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने पिछले मैच की हार को भुलाते हुए बुधवार को शानदार वापसी की और यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में यूनान के खिलाफ अमेरिका को 1-0 की बढ़त दिला दी। मौजूदा चैंपियन अमेरिका की ओर से खेलते हुए गॉफ ने यूनान की शीर्ष खिलाड़ी मारिया सकारी को 6-3, 6-2 से शिकस्त दी।

हार के बाद मजबूत वापसी

विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर काबिज गॉफ को इससे पहले ग्रुप चरण के अपने आखिरी एकल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें स्पेन की जेसिका बौज़ास मानेरो के खिलाफ 6-1, 6-7 (3), 6-0 से हार मिली थी। हालांकि, क्वार्टरफाइनल जैसे अहम मुकाबले में गॉफ ने आक्रामक और संतुलित खेल दिखाते हुए आलोचकों को करारा जवाब दिया।

साथियान | इंजीनियरिंग छोड़ टेबल टेनिस में बनाया करियर

कॉमनवेल्थ गेम्स में देश को दिलाया स्वर्ण

नई दिल्ली, एजेंसी। साथियान ज्ञानसेकरन भारत के एक बेहतरीन टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ज्ञानसेकरन ने लगातार दो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतकर भारत का नाम वैश्विक मंच पर रोशन किया था। साथियान ज्ञानसेकरन का जन्म 8 जनवरी 1993 को चेन्नई में हुआ था। साथियान ज्ञानसेकरन शिक्षाविदों के परिवार से हैं। उनके पिता सरकारी नौकरी में थे और जिम्बाब्वे में तैनात थे, जबकि मां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत थीं। वह अपने परिवार में पहली पीढ़ी के एथलीट हैं। टेबल टेनिस के प्रति साथियान का झुकाव बचपन से था। एस. रमन की कोचिंग में उन्होंने टेनिस की बारीकियां सीखीं। साथियान दाएं हाथ के आक्रामक खिलाड़ी हैं जो शेकहैंड ग्रिप का उपयोग करते हैं। टेनिस के साथ-साथ साथियान ने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा था और सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से आईटी में स्नातक किया, लेकिन जब करियर बनाने की बारी आई तो साथियान ने टेबल टेनिस को चुना और इस क्षेत्र में कड़ी मेहनत के साथ अपना नाम बनाया और वैश्विक स्तर पर सफलता हासिल की। 2016 में साथियान ने आईटीटीएफ चैलेंज बेल्जियम ओपन का पुरुष सिंगल्स खिताब जीता, जो यूरोपीय धरती पर किसी भारतीय का पहला आईटीटीएफ खिताब था। 2016 में दक्षिण एशियाई खेल में उन्होंने पुरुष डबल और पुरुष टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। 2017 में स्पेनिश ओपन जीतकर वे दो आईटीटीएफ प्रो टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। साथियान ने 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स और 2022 बर्मिंघम कॉमनेल्थ गेम्स में टीम गेम में गोल्ड मेडल जीता था। वहीं इन दोनों इवेंट में पुरुष डबल्स में उन्होंने रजत पदक जीता था। 2021 और 2023 एशियन चैंपियन में पुरुष टीम इवेंट में उन्होंने कांस्य पदक जीता था, जबकि 2021 एशियन चैंपियन में पुरुष डबल्स इवेंट में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2019 में वे विश्व रैंकिंग में 24वें स्थान पर पहुंचे, जो किसी भारतीय पुरुष पैडलर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग थी। 2021 टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया था। साथियान ने 2025 में डब्ल्यूटीटी फीडर विएंटियाने एकल का खिताब जीता। इसके अलावा, उन्होंने डब्ल्यूटीटी कंटेंडर लागोस में डबल्स गोल्ड और यूटीटी नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप जीती। टेबल टेनिस के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए साल 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

मलेशिया ओपन

पीवी सिंधू की जुझारू जीत, प्री-क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह

कुआलालंपुर, एजेंसी। लंबे समय तक चोट के कारण कोर्ट से दूर रहने के बाद वापसी कर रहीं भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधू ने बुधवार को मलेशिया ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट के महिला एकल के पहले दौर में संघर्षपूर्ण जीत दर्ज करते हुए प्री-क्वार्टरफाइनल में प्रवेश कर लिया। पूर्व विश्व चैंपियन 30 वर्षीय सिंधू ने चीनी ताइपे की सुंग शुओ युन को 51 मिनट तक चले मुकाबले में 21-14, 22-20 से शिकस्त दी।

चोट के बाद दमदार वापसी- सिंधू पिछले साल अक्टूबर में पैर की चोट से उबरने के लिए सभी BWF वर्ल्ड टूर प्रतियोगिताओं से हट गई थीं। इस मुकाबले में उन्होंने वापसी पर आत्मविश्वास भरा खेल दिखाया और कोर्ट पर अपनी लय को बखूबी संभाला।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड मजबूत

विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान पर काबिज सिंधू ने सुंग को करियर में दूसरी बार हराया और उनके खिलाफ अपना रिकॉर्ड 2-0 कर लिया। सिंधू की आक्रामकता और अनुभव निर्णायक साबित हुए।

8 पॉइंट का झटका

टूटेगा वर्ल्ड कप का सपना

● अगर बांग्लादेश ने नहीं मानी भारत को लेकर ICC की ये शर्त

नई दिल्ली, एजेंसी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बांग्लादेश की उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें उसने कहा था कि वह टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले भारत में नहीं खेलेगा. बांग्लादेश ने अपने मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट कराने की मांग की थी.

लेकिन अब आईसीसी ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में ही खेलने होंगे. आईसीसी ने कहा कि अगर बांग्लादेश ने ऐसा नहीं किया तो उसके अंक कटेंगे.

बांग्लादेश को भारत आना ही होगा

अब आईसीसी के इस तेवर के बाद बांग्लादेश के पास केवल दो विकल्प हैं. या तो वह पूरे वर्ल्ड कप का बहिष्कार करे या फिर आईसीसी की शर्त माने और भारत में आकर मैच खेले. अगर ऐसा नहीं किया तो ये वर्ल्ड कप उसके लिए खत्म ही समझो. क्योंकि उसे अपने हर मैच के अंक गंवाने पड़ेंगे. और विपक्षी टीम को वॉकओवर मिल जाएगा. यानी बिना खेले उसे दो अंक मिल जाएंगे.

8 अंक का झटका और वर्ल्ड कप का खेल खत्म

अगर बांग्लादेश ने भारत का दौरा नहीं किया तो बांग्लादेश को अंक गंवाने पड़ सकते हैं और भारत में होने वाले अपने सभी मैचों में उन्हें वॉकओवर देना पड़ सकता है, जिसके चलते बाकी टीमों को पूरे दो अंक मिल जाएंगे. ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश के 4 मैच निर्धारित हैं. हालांकि श्रीलंका टूर्नामेंट का सह-मेजबान है, लेकिन बांग्लादेश को अपने सभी ग्रुप स्टेज मुकाबले भारत में खेलने हैं. उनके चार में से तीन मैच कोलकाता में खेले जाएंगे, जबकि एक मुकाबला मुंबई में निर्धारित है. यानी उसे 8 अंक का नुकसान झेलना पड़ेगा.

आईएसएल

इंडियन सुपर लीग की तारीखों की घोषणा

अगले महीने इस दिन से शुरू होगा सत्र; खेल मंत्री ने किया एलान

नई दिल्ली, एजेंसी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) की तारीखों का एलान कर दिया है। आईएसएल का आगामी सीजन अब तक शुरू नहीं हो सका था, लेकिन कई बैठकों के बाद इस लीग के शुरू होने का रास्ता साफ हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के आगामी सत्र के तारीखों का एलान किया। आईएसएल की शुरुआत 14 फरवरी से होगी और इसमें सभी 14 क्लब हिस्सा लेंगे। वाणिज्यिक साझेदारों की कमी के कारण यह लीग अब तक शुरू नहीं हो सकी थी जिस कारण काफी विवाद भी हो रहा था। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने हाल ही में कहा था कि आईएसएल के तारीख की घोषणा आने वाले सप्ताह में होगी।

विवाद पर लगेगा विराम?

खेल मंत्री मांडविया ने कहा, आईएसएल को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन आज सरकार, फुटबॉल महासंघ और मोहन बागान व ईस्ट बंगाल समेत 14 क्लबों की बैठक हुई और हमने फैसला किया है कि आईएसएल 14 फरवरी से शुरू होगा। सभी क्लब इसमें भाग लेंगे। पिछले कुछ समय से भारतीय फुटबॉल को लेकर अदालत में चल रहे विवाद के कारण आईएसएल के आयोजन को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी जिस पर अब विराम लग गया।

आईएसएल संचालन परिषद बोर्ड का होगा गठन

एआईएफएफ अध्यक्ष कल्याण चौबे ने इस मौके पर बताया, 'आईएसएल के संचालन के लिए संचालन परिषद बोर्ड का गठन होगा। आईएसएल में 14 टीमों के 91 मैच एक चरण में होम (घरेलू) और अवे (प्रतिद्वंद्वी टीम का घरेलू मैदान) आधार पर खेले जाएंगे।' चौबे ने कहा कि मैच कहां होंगे, यह क्लब एआईएफएफ के साथ मिल कर तय करेंगे। उन्होंने कहा, 'आई लीग में 11 टीमों के बीच 55 मैच खेले जाएंगे जो आईएसएल के साथ ही आरंभ होगी। इसमें आईलीग-दो और आईलीग-तीन में 33 के बजाय 40 टीमें होंगी।' उन्होंने बताया कि आईएसएल के लिए 25 करोड़ रुपये का एक कैप (खर्च की सीमा) बनाया गया है जिसमें 10 प्रतिशत एआईएफएफ, 15 प्रतिशत क्लब 30 प्रतिशत व्यावसायिक साझेदार वहन करेंगे। चौबे ने कहा, 'जब तब व्यावसायिक साझेदार नहीं मिल जाता तब तक एआईएफएफ कुल 40 प्रतिशत खर्च वहन करेगा।' उन्होंने कहा कि एआईएफएफ का कुल योगदान 14 करोड़ रुपये होगा जिसमें 10 करोड़ आईएसएल और 3.2 करोड़ आई लीग के लिए होंगे। आईडब्ल्यूएल (इंडियन वुमेन लीग) का शत प्रतिशत फंड एआईएफएफ का होगा।

एशेज 5वां टेस्ट

ऑस्ट्रेलिया के पास 183 की बढ़त

इंग्लैंड की अच्छी शुरुआत, स्टोक्स चिंता के सबब

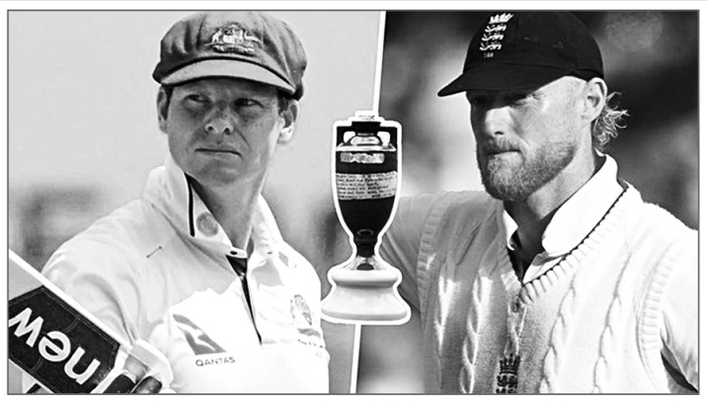

सिडनी, एजेंसी। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पांचवें और आखिरी टेस्ट के चौथे दिन बुधवार (7 जनवरी) को ऑस्ट्रेलिया के पहली पारी में 567 रन पर ऑल आउट होने के बाद बेन स्टोक्स की अगुआई वाली इंग्लैंड टीम ने अच्छी वापसी की। हालांकि, स्टोक्स की चोट ने इंग्लैंड की चिंता बढ़ा दी है। चौथे दिन लंच तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 80 रन बना लिए थे। वह ऑस्ट्रेलिया से 103 रन पीछे था। ओपनर बेन डकेट (48 गेंदों में 40 रन, जिसमें छह चौके शामिल हैं) और जैकब बेथेल (52 गेंदों में 28 रन, जिसमें चार चौके शामिल हैं) क्रीज पर थे। चौथे दिन का खेलने शुरू होने पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 124 ओवर में 518/7 था। इंग्लैंड की पहली पारी में 384 रन के जवाब में मेजबान टीम 134 रन से आगे थी। स्टीव स्मिथ (205 गेंदों में 129 रन, 15 चौके और एक छक्का) और ब्यू वेबस्टर (58 गेंदों में 42 रन, चार चौके) क्रीज पर थे। मेजबान टीम स्कोर में 49 रन और जोड़र पहली पारी में 567 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे उसे 183 रन की बढ़त मिली।

बेन स्टोक्स चोटिल

इंग्लैंड की चिंता कप्तान बेन स्टोक्स की चोट ने बढ़ा दी है। वह सिडनी में पांचवें और आखिरी टेस्ट के चौथे दिन 15 मिनट बाद ही दाहिनी जांघ को पकड़कर मैदान से बाहर चले गए। स्टोक्स बुधवार को अपने दूसरे ओवर में सुबह की 10वीं गेंद फेंकने के बाद रुके और तुरंत ड्रेसिंग रूम की ओर चले गए। वह अपने 28वें ओवर की चार गेंदें फेंक चुके थे। एक प्रवक्ता ने कहा, 'बेन स्टोक्स अभी दाहिने पैर की मांशपेशी में दिक्कत हुई है।'

ब्रिटिश जूनियर ओपन

खिताब जीतने से चूकीं अनाहत सिंह

बर्मिंघम, एजेंसी। भारत की शीर्ष स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह मंगलवार को बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में हुए मशहूर ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश के महिला अंडर-19 फाइनल में खिताब जीतने से चूक गईं। अनाहत को फाइनल में फ्रांस की दूसरी सीड लॉरेन बाल्टायन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।

HIMACHAL PRADESH JAL SHAKTI VIBHAG

NOTICE INVITING E-PROCUREMENT BID

Online bids on item rates basis are invited by the Executive Engineer Jal Shakti Division Baddi on behalf of Governor of Himachal Pradesh in electronic tendering system in two covers for the under mentioned work from the contractors/firms of appropriate class enlisted with H.P. Jal Shakti Vibhag.

S/ No.	Description	Estimated Cost (Rs.)	Earnest Money	Cost of Tender Form	Time Limit
1.	Consultancy Service for Augmentation of LWSS Baddi Town in Tehsil Baddi Distt. Solan (HP) (SH:- Preparation of project report for A/A& E/S, including field survey related study, estimation including topographical survey site plan, L-section, etc by outsourcing including drawing of all civil structure and hydraulic design).	2,80,084/-	5,602/-	500/-	Two Months
2.	Consultancy service for preparation of estimate for Construction of Office & Residential building of Assistant Engineer at JSV Sub-Division Chandi In Tehsil Kasauli Distt. solan (H.P.) (Sh:- Preparation of project report for A/A&E/S & Working estimate including field survey, related study, estimation including topographical survey Site Plan, L-Section, etc. by outsourcing including drawing of all civil structures and hydraulic design of all components and getting the same approved from the competent authority of the department as per direction of Engineer-in-Charge).	1,76,691/-	3,550/-	500/-	Six Months

KEY DATES SHALL BE AS UNDER: -

I	Site Visit	06-01-2026 to 14-01-2026 on working days time 10.00 A.M. to 4.00 P.M.
II	Date of online publication	06-01-2026 (6.00 P.M.)
III	Bid submission start date and time	06-01-2026 (6.00 P.M.)
IV	Bid submission end date and time	15-01-2026 (11.00 A.M.)
V	Date of opening bid i.e. eligibility criteria	15-01-2026 (11.30 A.M.)
VI	Date of opening of financial bid	Shall be intimated separately.

The tender forms and other detailed conditions can be downloaded from the website www.hptenders.gov.in.
For any clarification, please contact the O/O Executive Engineer, JSV Division Baddi.

Executive Engineer,
JSV Division, Baddi,
District Solan (HP)

R.No.5486/2025-2026

टी20 विश्व कप के लिए न्यूजीलैंड टीम घोषित, मिचेल सेंटनर होंगे कप्तान

नई दिल्ली, एजेंसी। टी20 विश्व कप 2026 के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने टीम का ऐलान कर दिया है। अनुभवी ऑलराउंडर मिचेल सेंटनर 15 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करेंगे। कप्तान के साथ ही मिचेल सेंटनर विश्व कप में सबसे अनुभवी खिलाड़ी भी होंगे। वह अपना 9वां आईसीसी इवेंट खेलेंगे। उनके साथ अनुभवी स्पिनर ईश सोढ़ी भी टीम का हिस्सा हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी का साल 2025 में शानदार प्रदर्शन रहा है। उन्हें भी टीम में जगह दी गई है। डफी ने पिछले साल तीनों फॉर्मेट मिलाकर 81 विकेट लिए थे। टी20 में गेंदबाजों की रैंकिंग में वह दूसरे नंबर पर हैं। तेज गेंदबाजी में डफी के साथ लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी और एडम मिल्ने को जगह दी गई है। जिमी नीशम भी तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में टीम में शामिल हैं।

ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल, ग्लेन फिलिप्स और रचिन रवींद्र टीम में गेंदबाजी और बल्लेबाजी को मजबूत करेंगे। विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी टिम सीफर्ट को दी गई है। काइल जैमीसन रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर शामिल हैं। जेमीसन को टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिल सकता है। टूर्नामेंट के दौरान फर्ग्यूसन और मैट हेनरी दोनों पैटरनिटी लीव लेने वाले हैं। इस दौरान जैमिसन की टीम में एंट्री हो सकती है। न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वाल्टर टी20 विश्व कप को लेकर उत्साहित हैं। वॉल्टर ने कहा, 'विश्व कप खास होते हैं, और भारत आधुनिक क्रिकेट की धड़कन है, और इससे बेहतर जगहें बहुत कम हैं। उन्होंने कहा कि मेगा इवेंट के लिए चुनी गई टीम संतुलित है। हमारे पास बैटिंग में बहुत पावर और स्किल है, क्वालिटी बॉलर हैं जो हालात के हिसाब से ढल सकते हैं, साथ ही पांच ऑल-राउंडर हैं जो सभी कुछ अलग लाते हैं। यह एक अनुभवी ग्रुप है, और खिलाड़ी सब-कॉन्टिनेंट में खेलने के लिए नए नहीं हैं, जो उनके लिए फायदेमंद होगा। न्यूजीलैंड को ग्रुप डी में अफगानिस्तान, कनाडा, साउथ अफ्रीका और यूएई के साथ रखा गया है। टीम का पहला मुकाबला 8 फरवरी को चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ होगा। विश्व कप भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाना है।

टी20 विश्व कप 2026 के लिए न्यूजीलैंड टीम

मिचेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डेरिल मिशेल, एडम मिल्ने, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी।
ट्रैवलिंग रिजर्व: काइल जैमीसन

न्यूज डायरी

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान एग्रीस्टैक पर पंजीकरण करवाना करें सुनिश्चित -उपायुक्त

हिन्द जनपथ

पंचकूला (ब्यूरो)। वितायुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा ने आज चंडीगढ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ विभिन्न विषयों पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

बैठक के उपरांत लघु सचिवालय के सभागार में उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होने उप निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को निर्देश दिए कि जिला में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियो एग्रीस्टैक पर अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। उन्होने किसानों से अपील की है की वे अपने गांव में कैंप में या नजदीकी सीएससी सैंटर पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, एसडीएम पंचकूला चंद्रकांत कटारिया, एसडीएम कालका संयम गर्ग, जिला राजस्व अधिकारी डॉ कुलदीप, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक रविन्द्र हुडडा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

सीमा सुरक्षा बल द्वारा सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक अलंकरण समारोह का आयोजन

हिन्द जनपथ

मोहाली (ब्यूरो)। सीमा सुरक्षा बल की पश्चिमी कमान ने मुख्यालय, सीमा सुरक्षा बल, पश्चिमी कमान, लखनौर कैम्पस, मोहाली (पंजाब) में आज सीमा सुरक्षा बल कर्मियों को उनकी सराहनीय सेवा हेतु पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए पदक अलंकरण समारोह का आयोजन किया।

इस अवसर पर पंजाब के माननीय राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में और ट्राइसिटी मोहाली, चण्डीगढ, पंचकुला में पदस्थ/कार्यरत सिविल एवं पुलिस प्रशासन के अन्य विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। समारोह आयोजन के दौरान, कुल 24 कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए, श्री सतीश एस खण्डारे, भारतीय पुलिस सेवा, अपर महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, पश्चिमी कमान ने दर्शकों को सीमा सुरक्षा बल के गौरवशाली अतीत के बारे में अवगत कराया और उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।

सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक उन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस के कर्मियों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने 18 से अधिक वर्षों की सराहनीयएवं उत्कृष्ट सेवाएं देश को समर्पित की हैं। यह चौथा अवसर है, जब यह समारोह द सिटी ब्यूटीफुल 'चण्डीगढ' में माननीय राज्यपाल पंजाब एवं प्रशासक चण्डीगढ की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।

दर्शकों को संबोधित करते हुए पंजाब के माननीय राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया जी ने शांति और युद्ध काल के दौरान भारत-पाक और भारत-बांग्लादेश सीमा को प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखने में बीएसएफ अधिकारियों और कर्मियों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीएसएफ न केवल देश की सीमाओं की ही रक्षा करती है बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा को भी बनाए रखने में पूर्णतह सक्षम है। साथ ही ऑपरेशन सिन्दूर में बी एस एफ की सक्रिय भूमिका तथा जम्मू व पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव राहत अभियान के बारे में भी विस्तार से बताया। समारोह के अंत में मुख्य अतिथि ने सभी पदक प्राप्तकर्ताओं को बधाई देते हुए उन्हें और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दीं।

ग्रुप-डी कर्मचारियों को ग्रुप-सी में पदोन्नति से जुड़े विवरण देने के निर्देश

हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा के मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्रुप-डी कर्मचारियों की पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले ग्रुप-सी पदों से संबंधित जानकारी तीन दिनों के भीतर उपलब्ध कराएं।

जारी पत्र के अनुसार, सभी विभागों को निर्धारित एक्सेल प्रारूप में ई-मेल के माध्यम से आवश्यक विवरण भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मांगी गई जानकारी में ग्रुप-सी में पदोन्नत किए जाने वाले पदों का नाम, विभागीय सेवा नियमों के अनुसार पात्रता मानदंड, ग्रुप-सी पदों की स्वीकृत संख्या, पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों की संख्या, रिक्त पदों की स्थिति, पात्र ग्रुप-डी कर्मचारियों की संख्या तथा कॉमन कैडर ग्रुप-डी से पदोन्नति हेतु उपलब्ध पदों का विवरण, संबंधित वेतनमान और अन्य टिप्पणियां शामिल हैं।

सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने की मुख्यमंत्री घोषणाओं और बजट घोषणाओं की समीक्षा

हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की नई सहकारिता नीति को क्रियान्वित करने की दिशा में हरियाणा गंभीरता से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के संकल्प और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के संग चलें, संग बढ़ें के मूल मंत्र के साथ हरियाणा की सहकारी समितियां अब अनाज भंडारण क्षेत्र में उतरेंगी।

सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए सीएम पैक्सों से शुरुआत करने तथा इच्छुक सहकारी समितियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उभारने के लिए भी शीघ्र ही समन्वय समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। सहकारिता मंत्री हरियाणा सिविल सचिवालय स्थित कमेटी कक्ष में सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेन्द्र कुमार एवं सभी सहकारी संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में अनाज भंडारण के लिए गोदाम निर्माण के उद्देश्य से हैफेड को नोडल एजेंसी बनाते हुए 10 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए अधिकृत किया गया है। इस दिशा में हैफेड द्वारा अब तक 3.35 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि 1.38 लाख मीट्रिक टन के लिए प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति को भेज दिए गए हैं।

सहकारी समितियां आत्मनिर्भर भारत – विकसित भारत संकल्प में अपना अहम योगदान दे सकें, इसके लिए सीएम पैक्सों को भी अनाज भंडारण क्षेत्र में अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में अब तक पंजीकृत सभी सीएम पैक्सों को इस संभावना के बारे में अवगत कराते हुए अवसर प्रदान किए जाएं, ताकि उन्हें व्यवहारिक तौर पर लाभ मिल सके।

जीरामजी योजना का उद्देश्य हर हाथ को काम और हर चेहरे पर मुस्कान लाना है : विपुल गोयल

- ग्रामीणों को मिलेगी 125 दिन के रोजगार की गारंटी : विपुल गोयल
- विकसित भारत-जी राम जी' योजना मनरेगा से बेहतर, कांग्रेस फैला रही है झूठ : विपुल गोयल
- कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने पलवल में प्रेसवार्ता कर जीरामजी योजना के उद्देश्यों के बारे में पत्रकारों से खुलकर चर्चा की

हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि वीबी-जीरामजी योजना स्थायी आजीविका की गारंटी है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा और गांवों में रोजगार और आत्मनिर्भर की नई क्रांति आएगी। श्री गोयल बुधवार को पलवल स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे।

विपुल गोयल ने कहा कि कांग्रेस के शासन में मनरेगा भ्रष्टाचार का केंद्र बन गई थी, लेकिन जीरामजी योजना पारदर्शी और और ग्रामीणों के लिए फायदा की योजना है। श्री गोयल ने वीबी जीरामजी योजना की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार ने ग्रामीणों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए रोजगार के दिनों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि मजदूरी के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी होती है तो लाभार्थी को अतिरिक्त मुआवजे का प्रावधान किया गया है। साथ ही बेरोजगारी भत्ते के नियमों को पहले से कहीं अधिक सख्त और प्रभावी बनाया गया है ताकि पात्र व्यक्तियों को उनका हक मिल सके।

मंत्री विपुल गोयल ने कहा अब गाँव के विकास की रूपरेखा दिल्ली से नहीं बल्कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं तैयार की जाएगी। योजना के तहत कम से कम 50 प्रतिशत कार्य सीधे ग्राम पंचायतों के माध्यम से करवाए जाएंगे। जॉब कार्ड जारी करने, परिवारों के पंजीकरण और काम के आवेदन लेने जैसी महत्वपूर्ण शक्तियां अब पूरी तरह से पंचायतों के पास होंगी।

श्री गोयल ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गाँवों में ही स्किल सेंटर और 'हाट' (बाजार) विकसित किए जाएंगे। बुवाई या कटाई के पीक सीजन के दौरान मजदूरों की कमी न हो इसके लिए राज्य सरकार साल में अधिकतम 60 दिनों तक योजना के कार्यों को स्थगित कर सकेगी। फील्ड स्टाफ (ग्राम रोजगार सहायक, मैट और फील्ड असिस्टेंट) के बेहतर संचालन के लिए प्रशासनिक खर्च को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया है।

श्री गायेल ने कहा कि भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। अब काम पर बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य होगी और कार्यों की जांच मोबाइल ऐप व सैटेलाइट के जरिए की जाएगी। इसके अतिरिक्त गाँव के नागरिकों को सोशल ऑडिट का अधिकार दिया गया है ताकि वे स्वयं विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकें।

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि कांग्रेस के शासन में मनरेगा में जमकर भ्रष्टाचार होता था, लेकिन जीरामजी योजना पूरी तरह से पारदर्शी है। उन्होंने कहा कि जीरामजी योजना को लेकर कांग्रेस झूठ फैला रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य इस अधिनियम के माध्यम से हर ग्रामीण हाथ को काम और हर ग्रामीण चेहरे पर मुस्कान लाना है।

महाग्राम योजना में अनियमितताएं पाए जाने पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने 2 एसडीओ और 1 जेई को सस्पेंड किया

हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोकनिर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा की अध्यक्षता में बुधवार को हरियाणा निवास, चंडीगढ़ में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रदेश में पेयजल आपूर्ति, महाग्राम योजना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) तथा आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए विभागीय तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में विभाग के मुख्य अभियन्ता श्री देवेन्द्र दाहिमा, सहित विभाग के प्रमुख अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता भी मौजूद थे, जबकि उपमंडल अभियंता और कनिष्ठ अभियंता ऑनलाइन जुड़े थे।

बैठक के दौरान महाग्राम योजना में अनियमितताएं पाए जाने पर कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने सख्त रुख अपनाते हुए 2 उपमंडल अभियंता (एसडीओ) और 1 कनिष्ठ अभियंता (जेई) को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने तथा 2 कार्यकारी अभियंता (एक्सईन) को चार्जशीट करने के निर्देश दिए। यह कार्रवाई डबवाली क्षेत्र के गांव गंगा से संबंधित मामले में की गई है, जहां महाग्राम योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों में गुणवत्ता को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि जनस्वास्थ्य विभाग से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही, भ्रष्टाचार या गुणवत्ता से समझौता किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महाग्राम योजना सहित सभी योजनाओं में कार्यों की गुणवत्ता की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए तथा फील्ड स्तर पर निरीक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जहां भी अनियमितता पाई जाएगी, वहां संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार अपने संकल्प पत्र को धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना है। इसके तहत सरकार 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मानक के अनुसार पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने के लिए पानी की सैंपलिंग की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत किया जाए तथा प्राप्त होने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर शिकायतों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पानी लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, ऐसे में इसके लिए विशेषतौर पर ध्यान रखा जाए।ब

हरियाणा पुलिस की बड़ी उपलब्धि: 12 मोस्ट वांटेड अंतरराष्ट्रीय अपराधी विभिन्न देशों से डिपोर्ट होकर गिरफ्तार, संगठित अपराध पर ऐतिहासिक प्रहार

हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के गठन के बाद राज्य में संगठित अपराध और अंतरराष्ट्रीय गैंग नेटवर्क पर सबसे प्रभावी और निर्णायक प्रहार देखने को मिला है। एसटीएफ ने यूएई, थाईलैंड, फिलीपींस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, कंबोडिया और अमेरिका सहित विभिन्न देशों से 12 मोस्ट वांटेड अपराधियों को डिपोर्ट करवाकर गिरफ्तार किया, जबकि एक अपराधी को जिला पुलिस ने दबोचा। कुल मिलाकर 13 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी हरियाणा पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सफलता मानी जा सकती है। वर्ष 2025 से अब तक यह एसटीएफ की छठीं बड़ी उपलब्धि है, जिसने यह सिद्ध किया कि विदेश में छिपे अपराधी भी हरियाणा पुलिस की पकड़ से बच नहीं सकते।

डीजीपी अजय सिंघल का सख्त संदेश: जीरो टॉलरेंस और त्वरित वैधानिक कार्रवाई

नव नियुक्त डीजीपी अजय सिंघल ने पदभार संभालते ही अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि संगठित अपराध, फिरौती, अवैध हथियारों और हिंसा से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की ढिलाई सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई अपराधी पुलिस पर हमला करता है या हथियार दिखाता है, तो पुलिस का संवैधानिक आत्मरक्षा अधिकार स्वतः सक्रिय हो जाता है और ऐसे मामलों में त्वरित व निर्णायक कार्रवाई करना अनिवार्य है। उन्होंने एसटीएफ के साहस, तकनीकी दक्षता और समन्वित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। इन कार्रवाइयों से जनता में सुरक्षा और विश्वास की भावना मजबूत हुई है तथा अपराधियों में कानून का भय और अधिक गहरा हुआ है। डिपोर्ट हुए अपराधियों के खिलाफ दर्ज गंभीर मामलों से एसटीएफ की सफलता और अधिक स्पष्ट होती है। इन 12 अपराधियों पर कुल 397 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें से 109 मामलों का निपटारा हो चुका है। थाईलैंड से डिपोर्ट तीन अपराधियों पर क्रमशः 61, 79 और 7 मामले दर्ज थे। यूएई से लाए गए दो अपराधियों पर 90 और 27 मामले दर्ज थे, जबकि फिलीपींस से डिपोर्ट अपराधी पर 38, कंबोडिया से 30 और अमेरिका से पकड़े गए अपराधियों पर क्रमशः 7 और 24 मामले दर्ज थे।

गीता ज्ञान की धरा पे कश्मीर के युवा हुए गदगद - गजेंद्र फौगाट

- पंचकुला के पीडब्लूडी विश्रामगृह में कश्मीरी युवाओं ने फौगाट संग किया संवाद
- हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलने की जताई इच्छा

हिन्द जनपथ

पंचकूला (ब्यूरो)। हरियाणा की पावन धरती पर गीता ज्ञान की परंपरा से रूबरू होकर कश्मीर से आए युवा गदगद नजर आए।

पंचकुला में आयोजित सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के दौरान कश्मीर के युवाओं और मुख्यमंत्री के ओएसडी प्रचार गजेन्द्र फौगाट समेत हरियाणा के सांस्कृतिक प्रतिनिधियों के बीच सार्थक संवाद हुआ।

कार्यक्रम में ओएसडी व हरियाणा कला परिषद के निदेशक गजेंद्र फौगाट ने कहा कि हरियाणा की गीता ज्ञान परंपरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों की भी मजबूत धरोहर है। इस धरा से जुड़कर कश्मीर के युवाओं में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ है।

गजेंद्र फौगाट ने कहा कि हरियाणा और कश्मीर की लोकसंस्कृति में गहरी समानताएं देखने को मिलती हैं। दोनों क्षेत्रों के लोक रागों, सुरों और भावों में अद्भुत साम्य है, जो देश की सांस्कृतिक एकता को और मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक संवाद युवाओं को एक-दूसरे की परंपराओं, मूल्यों और जीवन दृष्टि को समझने का अवसर प्रदान करते हैं।

इस मौके पर कश्मीर से आए युवाओं ने हरियाणवी दूध व गाजरपाक का आनंद उठाया, उन्होंने फौगाट संग हरियाणवी व उर्दू गीत भी गाऐ तथा भविष्य में ऐसे और कार्यक्रम में आने की इच्छा जताई। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रीय अखंडता और आपसी सद्भाव को मजबूत करने का संकल्प लिया।

इस मौके पर समन्यवक नरेंद्र, देवेंद्र चिड़ाना, साहिल सलूजा, अनिल, रवि बेदी समेत अनेकों गणमान्यजन उपस्थित थे।

हाथरस प्रकरण के विरोध में रावाधस का जंतर मंतर दिल्ली में ज़ोरदार प्रदर्शन

हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हाथरस- उत्तर प्रदेश के मनीषा वाल्मीकि, प्रकरण को लेकर राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज (रावाधस) रजि. के राष्ट्रीय मुख्य संचालक संगम कुमार वाल्मीकि और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पूजा उज्जैनवाल के नेतृत्व में दिल्ली जंतर मंतर पर ज़ोरदार प्रदर्शन किया गया। रोष प्रदर्शन में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष/ संस्थापक वीर दिलबाग टांक आदिवासी और जिला हाथरस-उत्तर प्रदेश प्रकरण के अधिवक्ता महमूद प्राचा ने बुलंद आवाज में पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग उठाई। साथ ही उत्तर प्रदेश बरेली से आए राष्ट्रीय धर्म आचार्य श्री श्री 108 महंत ब्रह्मदास महाराज जी और पंजाब प्रधान अमित रंधावा, दिल्ली सचिव किशन कश्यप, उत्तराखंड राष्ट्रीय प्रचार मंत्री अशोक कुमार, राष्ट्रीय झाड़ू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लव कुश उर्फ़ लाखन ,भीम शेरनी डॉ.रितु सिंह,रामसिंह चानालिया अंबाला जी ने अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर देश में जगह जगह आंदोलन कराने का आव्हान किया।

इसी दौरान मुख्य रूप दिल्ली उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड से आए लोगों ने बढ़ चढकर भाग लिया।

संगम कुमार वाल्मीकि ने हाथरस में एक दलित लड़की के साथ जो दरिंदगी हुई, उससे पूरा देश गुस्से में है। लड़की के साथ हैवानगी करने वालों को फांसी देने की मांग उठ रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा यदि 15 दिनों में मनीषा वाल्मीकि हाथरस कांड के प्रकरण में उचित कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वह पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर वाल्मीकि जागो अभियान की शुरुआत कर समाज के अंतिम सदस्य तक पहुंचकर वाल्मीकि समाज के तमाम विषयों को एकत्रित कर मौजूदा सरकार का जगह जगह से वहिष्कार करेंगे।

रोष प्रदर्शन के दौरान दिल्ली से राजेश पार्चा, सचिन कुमार वाल्मीकि जिलाध्यक्ष शाहजहांपुर, निखिल वाल्मीकि, राज वाल्मीकि, रवींद्र पार्चा गाजियाबाद, मंजू, प्रदीप पुहाल अध्यक्ष चंडीगढ़, विशाल गाजियाबाद, जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र मौजूद रहे।

जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : आरती सिंह राव

हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई का आयोजन कर राज्य के विभिन्न जिलों से आए नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य सेवाओं सहित अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर पहुंचे।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति की बात को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

आरती सिंह राव ने जनसुनवाई के दौरान मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी शिकायतों का निपटारा तय समय सीमा के भीतर किया जाए और इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि जिन मामलों में तुरंत कार्रवाई संभव है, उनमें तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए और जटिल मामलों में संबंधित व्यक्ति को स्थिति से अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करना ही सुशासन की पहचान है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जनसुनवाई जैसे कार्यक्रम सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम हैं। इससे न केवल समस्याओं की सही जानकारी मिलती है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है।

पारदर्शी चयन प्रक्रिया पर उठाए जा रहे आरोप निराधार : हरियाणा लोक सेवा आयोग

हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा लोक सेवा आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग के संज्ञान में आया है कि हाल के दिनों में आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर एक झूठा और भ्रामक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है तथा आयोग को राज्य सेवाओं में नियुक्तियों हेतु परीक्षाएं आयोजित करने का संवैधानिक दायित्व सौंपा गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि आयोग द्वारा की गई भर्तियां न्यायिक जांच की कसौटी पर खरी उतरी हैं, जो आयोग द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता का प्रमाण है। आयोग को प्राप्त होने वाले सभी अभ्यावेदन, शिकायतों एवं सुझावों पर विधिवत विचार किया जाता है तथा आवश्यक कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, चयन प्रक्रिया से संबंधित समस्त जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षण की गुणवत्ता को लेकर आयोग के माननीय अध्यक्ष से संबंधित जो टिप्पणियां प्रसारित की जा रही हैं, वे पूर्णतः असत्य, निराधार एवं भ्रामक हैं। यह कुछ निहित स्वार्थों द्वारा आयोग की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आयोग शैक्षणिक जगत (अकादमिक समुदाय) को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखता है तथा उनके सक्रिय सहयोग के बिना इतनी व्यापक और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया संभव नहीं होती। प्रवक्ता ने दोहराया कि आयोग द्वारा की गई सभी भर्तियां पूर्णतः मेरिट के आधार पर की गई हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को आयोग से संबंधित किसी भी विषय पर कोई शंका या आपत्ति है, तो वे आयोग के सचिव के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि उनकी शिकायतों का समाधान किया जा सके। इससे उन्हें वास्तविक स्थिति की जानकारी भी प्राप्त होगी और वे चयन प्रक्रिया को बाधित करने वाले झूठे नैरेटिव से भ्रमित नहीं होंगे।

लोक निर्माण विभाग स्वयं को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करे: रणबीर गंगवा

- सड़क एवं बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे करवाने के निर्देश
- काम में देरी करने की लापरवाही बरतने वाली गुरुग्राम और थानेसर की एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने के दिये निर्देश

हिन्द जनपथ

चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश में भवन और सड़कें वन-स्टैंडर्ड हों तथा लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) स्वयं को एक मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित करे। इसके लिए विभाग के अधिकारी पूरी योजना के साथ काम करें। जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, और उनकी समस्याओं के तुरंत समाधान की दिशा में भी काम हो।

कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने बुधवार को हरियाणा निवास में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई निर्देश दिए है। बैठक में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के अंतर्गत सड़कों से संबंधित कार्यों, सफेद पट्टी (रोड मार्किंग), प्रस्तावित मॉडल रोड्स तथा भवन एवं सड़क से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

लेटलतीफी करने वालों पर एक्शन होगा: गंगवा

बैठक के दौरान अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि कुछ स्थानों पर एक ही ठेकेदार द्वारा कई-कई कार्य लेने के कारण परियोजना समय पर पूरा नहीं हो पा रही। इस पर मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने काम को 1 साल तक भी पूरा नहीं कर पाने वाली एजेंसी पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने थानेसर और गुरुग्राम क्षेत्र की ऐसी एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि नियमानुसार अधिक टेंडर कार्य लेना गलत नहीं है, लेकिन सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे होने चाहिए। किसी भी प्रकार की लेटलतीफी या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ठेकेदार की लेटलतीफी का खामियाजा जनता को क्यों भुगतना पड़ता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि अगर कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं तो समय पर प्रोजेक्ट पूरा हो। मंत्री श्री गंगवा ने निर्देश दिए कि किसी भी कार्य के पूर्ण होने के तीन माह के भीतर वित्तीय क्लोजिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी एजेंसी को भुगतान को लेकर परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में देरी स्वीकार्य नहीं है और इसके लिए सभी अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करनी होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि हेडक्वार्टर से समय-समय पर टीमें भेजकर कार्यों की गुणवत्ता की जांच की जाए तथा गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। अधिक माइलेज वाले टेंडरों पर विशेष नजर रखने, खराब हालत की सड़कों की नई सड़क बनने तक मरम्मत सुनिश्चित करने तथा पिछली डीएलपी अवधि की सड़कों की नियमित निगरानी के निर्देश भी दिए गए। बैठक में बताया गया कि हरियाणा में 30403 किलोमीटर लंबी सड़क है।